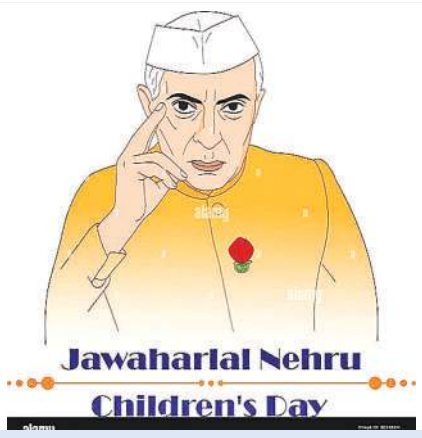
रायपुर, जबलपुर, कटनी, भोपाल, मंडला,इंदौर, मुंबई, दिल्ली, नरसिंहपुर, सिवनी से एक साथ प्रकाशित

yashbharat.co.in

नये जमाने के साथ..

यश भारत

● वर्ष-1 अंक-172 ● रायपुर ● शनिवार , 14 नवम्बर , 2026 ● मूल्य- 4 रुपए ● पृष्ठ-8 ● कार्तिक शुक्ल पक्ष 6 ● विक्रम संवत् 2083



काजीरंगा के पास भीषण सड़क हादसा

मिनी बस -कंटेनर भिड़े, 23 की मौत, 20 घायल





काजीरंगा, एजेंसी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क के पास शुक्रवार को भीषण सड़क हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर कोहोरा रेंज के अंतर्गत रंगाजन इलाके में हाथीकुली टी एस्टेट के पास हुआ। यहां यात्रियों से भरी एक मिनी बस और कंटेनर ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। पुलिस और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कई यात्री बस के अंदर ही फंस गए। राहत एवं बचाव दल ने बस को काटकर शवों को बाहर निकाला। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में 35 से अधिक लोग सवार थे। मृतकों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्नानिल डेका ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी। शुरुआत में 20 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई थी, लेकिन राहत एवं बचाव कार्य के दौरान मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। कोहोरा मॉडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बोकोखात और गोलाघाट के अस्पतालों में भेजा गया। कुछ घायलों को बेहतर उपचार के लिए जोरहाट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में कई कॉलेज के छात्र भी प्रभावित हुए हैं। बताया गया कि छात्र अपनी कक्षाएं समाप्त होने के बाद लौट रहे थे, तभी उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी मिलते ही असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा घटनास्थल पर पहुंचे। वह इसी क्षेत्र के विधायक भी हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से घायलों के उपचार तथा बचाव अभियान की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में मिनी बस की तेज रफ्तार सामने आई है। काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास वाहनों की गति को लेकर प्रतिबंध लागू हैं। आशंका है कि मिनी बस इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस सामने से आ रहे कंटेनर ट्रक से जा भिड़ी।



23 वाहनों में लगी आग, 3 भारतीय समेत 14 की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह के पास भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। मृतकों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। हादसा उस समय हुआ, जब एक बेकाबू ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और देखते ही देखते लपटों ने आसपास मौजूद वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यूएई के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक, हादसा गुरुवार आधी रात से कुछ देर पहले पूर्वी अमीरात की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ। उस समय यातायात धीमा था और कई वाहन आगे बढ़ने के लिए इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक ने आगे चल रहे वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद पलटा हुआ ट्रक सड़क पर धीमी गति से चल रहे और रुके हुए कई वाहनों से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों में आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण कई लोग गाड़ियों के भीतर फंस गए। हादसे में पांच ट्रकों सहित कुल 23 वाहन शामिल थे। आग लगते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस, पैरामेडिकल और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं। बचाव दल ने आग पर काबू पाने के साथ वाहनों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।

छठ महापर्व शुरू

40 लाख श्रद्धालु बिहार लौटे 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य



नई दिल्ली,यशभारत। लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ शुरू हो रहा है। चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे। पर्व का समापन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। छठ को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों की साफ-सफाई, सजावट और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं।

छठ पर्व को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले बिहार के लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। दावा किया जा रहा है कि देशभर से करीब 40 लाख लोग बिहार लौट चुके हैं। पटना जंक्शन सहित राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पिछले पांच दिनों से यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। गुजरात के सूरत से ही दो दिनों में करीब 60 हजार लोग अपने गृह नगरों के लिए रवाना हुए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए गुजरात से 43 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हरियाणा के अंबाला कैंट सहित कई रेलवे स्टेशनों पर भी यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है।

दिल्ली में इस बार छठ पूजा के लिए मूनक नहर के दोनों किनारों पर करीब 11 किलोमीटर लंबा विशाल घाट विकसित किया गया है। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसका उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में छुट्टी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर 15 और 16 नवंबर को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। यहां छोटे-बड़े 54 घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़े तालाब के शीतलदास घाट सहित विभिन्न जलाशयों पर व्रती सूर्य को अर्घ्य देंगे। देश के अलग-अलग हिस्सों में रह रहे पूर्वांचल और बिहार के परिवारों में भी पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है।

मणिपुर में उग्रवादियों की अंधाधुंध फायरिंग

दो महिलाओं समेत 4 की मौत

उखरुल, एजेंसी। मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को उग्रवादियों ने दो वाहनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है

पुलिस के मुताबिक, वारदात इम्फाल-उखरुल मार्ग पर न्यू हेवन इलाके में हुई। हमले के दौरान दोनों वाहनों में सवार लोगों को निशाना बनाया गया। फायरिंग इतनी भीषण थी कि वाहनों के आगे के शीशों पर गोलियों के निशान मिले हैं। मृतकों में दो पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं।इस घटना से एक दिन पहले भी मणिपुर के दो इलाकों में गोलीबारी की घटनाएं सामने आई थीं। कांगपोकपी जिले के ताफोउ कुकी गांव और सेनापति जिले के कैलेंगजांग के पास हुई फायरिंग में 42 वर्षीय एक कुकी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि दो पुरुष घायल हुए थे। लगातार हो रही हिंसक घटनाओं ने पहाड़ी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और सामुदायिक तनाव को लेकर चिंता बढ़ा दी है।इस साल फरवरी से अब तक पहाड़ी जिलों में कुकी और नागा समुदायों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 50 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, मई 2023 में घाटी के मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी समुदायों के बीच शुरू हुए जातीय संघर्ष का असर अब तक बना हुआ है। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग लापता बताए गए हैं। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा है।

मेट्रो में आम यात्री की तरह सफर पर निकले पीएम मोदी, काउंटर से खरीदा



बेंगलुरु, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक दौरे के दौरान बेंगलुरु मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मेट्रो स्टेशन के टिकट काउंटर से खुद टिकट खरीदा और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ मेट्रो में सफर किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में करीब 15,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु अब 100 किलोमीटर से अधिक मेट्रो नेटवर्क वाला देश का तीसरा शहर बन गया है। शाम को प्रधानमंत्री ने मैसूरु में कॉसमॉस प्लेनेटोरियम का उद्घाटन किया इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक सदियों से योग और आध्यात्मिक साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। इस धरती ने अनेक योग गुरुओं और विद्वानों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और संतुलित समाज का आधार है।प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेलवे, ऊर्जा सुरक्षा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे अब गुलामी की सोच को पीछे छोड़कर आधुनिक सुविधाओं की ओर बढ़ रहा है। कर्नाटक के 60 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किया जा चुका है। इन स्टेशनों पर यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध जैसी परिस्थितियों के दौरान भारत को ऊर्जा क्षेत्र में पिछले एक दशक में उठाए गए कदमों का लाभ मिला है।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर फोन टैपिंग का आरोप, फिर दी बहस की चुनौती

नई दिल्ली, एजेंसी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर आयोजित आस्क मी सेशन में राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए दावा किया कि विदेशी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े आरोपों के सबूत उनके फोन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है। राहुल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को आमने-सामने बहस की चुनौती देते हुए कहा कि यदि दोनों के बीच सीधी बातचीत हो जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पिछले 12 दिनों में यह सातवीं बार है, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है।



इंस्टाग्राम सेशन के दौरान एक यूजर ने राहुल गांधी से पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी आरोप लगाते हैं कि उन्हें विदेश से मदद मिल रही है, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं। इन दोनों दावों के समर्थन में क्या सबूत हैं? इस पर राहुल ने कहा कि उनके फोन में ही सभी आरोपों से जुड़े सबूत मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि आमने-सामने की बहस में यह स्पष्ट हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देश विरोधी कौन है और कौन कब से ऐसी गतिविधियों में शामिल है। राहुल ने कहा कि उनके पास ऐसी कई अन्य जानकारियां भी हैं, जिनके बारे में वह जानते हैं और जो उनके मोबाइल फोन में मौजूद हैं। एक अन्य सवाल में पूछा गया कि भाजपा संसद में बहस की बात कर रही है, जबकि राहुल सार्वजनिक मंच पर बहस की मांग क्यों कर रहे हैं? इस पर उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में कई मुद्दों पर बोलने की कोशिश करने के बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल ने किसान कानूनों, वोट चोरी, सावरकर, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एप्स्टीन से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें इन विषयों पर संसद में अपनी बात रखने से रोका गया।

इसरो को बड़ी कामयाबी, एलवीएम-3 के तीसरे स्टेज का ग्राउंड टेस्ट सफल

श्रीहरिकोटा, एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने भारी प्रक्षेपण यान एलवीएम-3 के तीसरे स्टेज का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले दो मिशनों के दौरान इसी स्टेज में तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसरो ने इन खामियों की विस्तृत जांच के बाद स्टेज के डिजाइन में बदलाव किया और इसे नए सिरे से तैयार कर परीक्षण किया। नए संस्करण की सफलता से एलवीएम-3 रॉकेट की उड़ान क्षमता को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है।

पीओके में यात्री वैन नदी में गिरी, 11 लोगों की मौत



इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र में यात्री वैन के नदी में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हुए हैं। हादसा उस समय हुआ, जब वैन गिलगित से घिजर जिले की यासीन घाटी जा रही थी। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हादसा गुरुवार शाम मोर्काह पुल के पास हुआ। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वैन यासीन नदी में जा गिरी। दुर्घटना के बाद बचाव दल को मौके पर बुलाया गया। बचावकर्मियों ने नदी से 10 यात्रियों के शव निकाले। इनमें दो महिलाएं शामिल थीं। इसके अलावा तीन घायलों को भी बाहर निकाला गया। घायलों में एक बच्चा भी था। सभी को उपचार के लिए गुपिस सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक, उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल बच्चे की भी मौत हो गई। इसके बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। दो अन्य घायलों का इलाज किया जा रहा है। मृतक और घायल सभी यासीन घाटी के निवासी बताए गए हैं।

महादेव सट्टा कांडः सौरभ चंद्राकर 19 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर

रायपुर, यशभारत। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रिमांड पर सौंप दिया है। अदालत ने ईडी की रिमांड अर्जी स्वीकार करते हुए 19 नवंबर तक पूछताछ की अनुमति दी है। इससे पहले शुक्रवार सुबह पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सौरभ चंद्राकर को हथकड़ी लगाकर रायपुर जेल से कोर्ट लेकर पहुंची। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आरोपी की पेशी के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।

अदालत में पेशी के बाद ईडी ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसकी रिमांड को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। नॉन-बेलेबल वारंट और जांच एजेंसी की मांग पर दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद ईडी की अर्जी स्वीकार कर ली और 19 नवंबर तक आरोपी को ईडी की हिरासत में सौंपने का आदेश दिया।

इससे पहले आठ दिन की कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद गुरुवार को सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत में



पेश किया गया था। उस समय ईडी ने दोबारा कस्टडी की मांग नहीं की थी और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का अनुरोध किया था। अदालत ने उसे 19 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। गुरुवार को हाई सिक्योरिटी के बीच उसे कोर्ट से जेल पहुंचाया गया था। जेल के भीतर जाते समय उसके हाथ में एक झोला भी दिखाई दिया था। इसके बाद शुक्रवार को ईडी ने दोबारा कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए उसे अपनी हिरासत में लेने की मांग की, जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी। ईडी की पिछली आठ दिन की पूछताछ में महादेव ऐप के सट्टा नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए कथित लेनदेन और प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई थी। जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि ऑनलाइन सट्टे से अर्जित रकम किन-किन लोगों तक पहुंचाई गई और इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने में किन लोगों की भूमिका रही। साथ ही कथित तौर पर किन अधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों को संरक्षण के बदले रकम दी गई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।अब नई रिमांड के दौरान ईडी सौरभ चंद्राकर से इन सभी पहलुओं पर विस्तार से पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी का मुख्य फोकस सट्टे से होने वाली कमाई के वित्तीय लेनदेन, हवाला नेटवर्क, पैनल संचालकों और कथित संरक्षण तंत्र की कड़ियां जोड़ने पर रहेगा। पूछताछ में सामने आने वाली जानकारियों के आधार पर इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका और अवैध कारोबार के नेटवर्क को लेकर आगे की जांच की दिशा तय हो सकती है।

रायपुर केंद्रीय जेल में सुरक्षा का हाई अलर्ट

बंदियों से कर्मचारियों तक की होगी सघन तलाशी

रायपुर, यशभारत। रायपुर केंद्रीय जेल में गांजा और मोबाइल फोन की तस्करी रोकने के लिए जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जेल के भीतर प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने की कोशिशों के सामने आने के बाद अब बंदियों, कर्मचारियों, मुलाकातियों और जेल परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच की जाएगी। जेल अधीक्षक ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, जेल में कपड़ों के भीतर सिलकर गांजा और मोबाइल फोन पहुंचाने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा की है। इसके तहत जेल में बंदियों से मिलने आने वाले परिजनों और परिचितों को भी बिना गहन जांच के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुलाकात कक्ष में आने वाले लोगों की तलाशी के साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले सामान की भी बारीकी से जांच होगी। अदालत में पेशी के लिए बाहर जाने वाले बंदियों की जेल से निकलते समय और पेशी के बाद वापस लौटने पर मुख्य द्वार पर सघन तलाशी ली जाएगी। पहले से लागू सुरक्षा प्रक्रियाओं को भी अब अधिक मुस्तैदी और सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।



जेल परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सबसे पहले गार्ड प्रभारी वाहन की जांच करेंगे। इसके बाद मुख्य द्वार पर तैनात गेट कीपर, मुख्य प्रहरी और प्रहरी संयुक्त रूप से वाहन तथा उसके चालक की बारीकी से तलाशी लेंगे। दोनों स्तरों पर जांच पूरी होने के बाद ही वाहन को जेल परिसर के भीतर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहनों के जरिए प्रतिबंधित सामग्री जेल के अंदर पहुंचाने की किसी भी कोशिश को नाकाम करना है।

जेल प्रशासन ने बंदियों की बैरकों और उनके सामान की नियमित सघन तलाशी लेने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही जेल के आंतरिक परिसरों का लगातार निरीक्षण किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री छिपाकर रखने की संभावना को खत्म किया जा सके। सुरक्षा व्यवस्था में तैनात मुख्य प्रहरी सहित अन्य सिविल कर्मचारियों को भी जेल द्वार से प्रवेश और बाहर निकलने के दौरान अनिवार्य रूप से तलाशी से गुजरना होगा। यानी अब जांच के दायरे में केवल बंदी और मुलाकाती ही नहीं, बल्कि जेल के कर्मचारी भी रहेंगे।

तलाशी के दौरान गांजा, मोबाइल फोन या अन्य कोई प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य किया गया है। उप जेल अधीक्षक को सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेल प्रशासन का यह कदम जेल के भीतर नशीले पदार्थों और मोबाइल फोन की अवैध पहुंच पर अंकुश लगाने तथा सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रेलवे आरएसी टिकट व्यवस्था खत्म करने पर कर रहा विचार

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरएसी (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) टिकट व्यवस्था में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इस व्यवस्था को खत्म करने की संभावना भी तलाशी जा रही है। यदि ऐसा होता है तो लाखों रेल यात्रियों को राहत मिल सकती है। फिलहाल आरएसी टिकट के तहत एक ही बर्थ पर दो यात्रियों को सफर करने की अनुमति दी जाती है। रेलवे में जब आरक्षित सीटों की मांग बढ़ जाती है और सभी यात्रियों को पूरी बर्थ उपलब्ध नहीं हो पाती, तब आरएसी टिकट जारी किए जाते हैं। इस व्यवस्था में दो यात्रियों को एक ही बर्थ पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है। दोनों यात्रियों को आधी-आधी जगह



मिलती है। रात के समय उन्हें इसी सीमित जगह में सोना पड़ता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा में काफी परेशानी होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों की सुविधा से जुड़ी चिंताओं के चलते रेलवे इस व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि जब किसी यात्री को सोने के लिए पूरी बर्थ उपलब्ध नहीं होती, तो उससे पूरी यात्रा का किराया लेना उचित नहीं है। इसी आधार पर मौजूदा नियम में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है।

शुभांक-8-3-4

दुर्ग के पोटियाकला में बजबजाती नालियों की बदबू से क्षेत्रवासी तंग



यश भारत

दुर्ग । शहर के पोटियाकला वार्ड क्रमांक 54 में जहा पीलिया का प्रकोप है वही दूसरी तरफ क्षेत्र की नालियां बजबजा रही है, जिससे निकलने वाली बदबू लोगो के घरों तक पहुच रही है, पोटियाकला में बजबजाती नालियों से लोग परेशान, घरों तक पहुंच रही बदबू

दुर्ग। शहर के पोटियाकला वार्ड क्रमांक 54 में एक ओर पीलिया के बढ़ते मामलों ने क्षेत्रवासियों की चिंता बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी ओर इलाके की बजबजाती नालियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। नालियों में जमा गंदगी और गंदे पानी से उठने वाली दुर्गंध आसपास के घरों तक पहुंच रही है। इसके चलते रहवासियों को घरों में रहना भी मुश्किल हो रहा है।

क्षेत्र में पहले ही 9 बच्चों के पीलिया से संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में नालियों की बदहाल स्थिति और साफ-सफाई की कमी से स्थानीय लोगों में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। रहवासियों का कहना है कि यदि समय रहते नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।

जल, जंगल और जमीन के अधिकार से सशक्त हो रहे बीजापुर के आदिवासी परिवार, 18,248 वन अधिकार पत्र वितरित

बीजापुर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बीजापुर जिले में आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में वन अधिकार अधिनियम के तहत किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आए हैं। जिले में अब तक व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के अंतर्गत कुल 18,248 मान्यता पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इससे हजारों आदिवासी परिवारों को जल, जंगल और जमीन से जुड़े उनके पारंपरिक अधिकारों की कानूनी मान्यता मिली है।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन से वनांचल के आदिवासी परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के साथ आजीविका के नए अवसर मिल रहे हैं। वर्षों से वनभूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर समुदायों को अधिकारों की मान्यता मिलने से उनके बीच आत्मविश्वास बढ़ा है। साथ ही ग्राम सभाओं की भूमिका भी मजबूत हुई है।

जिले में अब तक 15,120 व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। इनके माध्यम से 19,925.214 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि पर पात्र हितग्राहियों के अधिकारों को मान्यता दी गई है। विकासखंडवार आंकड़ों के अनुसार भैरमगढ़ में 6,660, उसूर में 3,477, बीजापुर में 2,750 और भोपालपटनम में 2,233 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इससे परंपरागत रूप से वनभूमि पर खेती करने वाले परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिलने के साथ कृषि और आजीविका को आगे बढ़ाने का आधार मिला है।



इसी तरह सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत जिले में 2,831 मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। इनके माध्यम से 62,961.124 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र को सामुदायिक अधिकारों के तहत मान्यता प्रदान की गई है। इसमें भैरमगढ़ विकासखंड में 880, बीजापुर में 714, भोपालपटनम में 621 और उसूर में 616 मान्यता पत्र शामिल हैं। इन अधिकारों से स्थानीय समुदायों को पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाले वन क्षेत्रों और संसाधनों के संरक्षण एवं उपयोग में वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बीजापुर जिले में इसके अंतर्गत 297 मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। इसके माध्यम से ग्राम सभाओं को मान्यता प्राप्त वन संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है। स्थानीय समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान और आवश्यकताओं के अनुरूप वन संसाधनों के सतत उपयोग तथा जैव विविधता के संरक्षण में भागीदारी निभा रहे हैं।

बीजापुर जैसे वनांचल जिले में कृषि, लघु वनोपज संग्रहण और वन आधारित गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार प्राप्त परिवार पात्रतानुसार विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर कृषि और आजीविका गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं सामुदायिक वन अधिकारों से ग्राम स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और पारंपरिक आजीविका को सुरक्षित रखने की संभावनाएं बढ़ी हैं।

जनजातीय गौरव दिवस महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, त्याग और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के उनके योगदान को याद करने का अवसर है। उन्होंने आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार तथा स्वाभिमान के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया था। वन अधिकार अधिनियम के माध्यम से पारंपरिक अधिकारों को कानूनी मान्यता देने की पहल उनके विचारों और अधिकार-संपन्न समाज के संकल्प को आगे बढ़ाती है।

बीजापुर जिले में वन अधिकार पत्रों का वितरण केवल भूमि और संसाधनों पर अधिकार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समुदायों की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और ग्राम सभाओं की भागीदारी को मजबूत करने का माध्यम भी बन रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर जिले की यह उपलब्धि जल, जंगल और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण के साथ आदिवासी समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जशपुर जिले की प्रारंभिक मतदाता सूची जारी, 6.30 लाख से अधिक मतदाता दर्ज; 11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

जशपुरनगर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर जशपुर जिले की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। जारी सूची के अनुसार जिले में कुल 6 लाख 30 हजार 876 मतदाता दर्ज हैं। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन किया जा सकेगा। इस संबंध में 12 नवंबर को कलेक्टर सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारंभिक मतदाता सूची की एक-एक प्रति और सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई। विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या के अनुसार जशपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख 20 हजार 176, कुनकुरी में 1 लाख 94 हजार 713 और पत्थलगांव में 2 लाख 15 हजार 987 मतदाता दर्ज हैं। इसके अलावा जिले में 1,747 सेवा निर्वाचक भी शामिल हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे एवं आपत्तियां 11 दिसंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इनका निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा।

जशपुर ओलंपिक 2026 का भव्य आगाज, आठ विकासखंडों के 2 हजार खिलाड़ी दिखाएंगे खेल प्रतिभा

जशपुरनगर। जिले में खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर मंच देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जशपुर ओलंपिक 2026 का शुक्रवार को रणजीता स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। दो दिवसीय इस आयोजन में जिले के सभी आठ विकासखंडों के जूनियर और सीनियर वर्ग के करीब 2 हजार खिलाड़ी 12 खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए विधायक गोमती साय ने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम भावना विकसित करने का माध्यम भी है। खिलाड़ियों को सफलता हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास, कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जशपुर के ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जशपुर ओलंपिक जैसे आयोजन इन प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से हार-जीत की चिंता किए बिना खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का आह्वान किया।

प्रतियोगिता के पहले दिन जूनियर वर्ग के लगभग 1100 बालक-बालिका खिलाड़ी मैदान में उतरे। वहीं दूसरे दिन सीनियर वर्ग के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। आयोजन में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, कराते, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और रस्साकशी सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।

एथलेटिक्स में 100, 200 और 400 मीटर दौड़ के साथ लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, जैवलिन थ्रो और 4म100 मीटर रिले रेस शामिल हैं।

दुर्ग के पोटियाकला में पीलिया का प्रकोप, 9 बच्चे संक्रमित; स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया सर्वे



यश भारत

दुर्ग। शहर के पोटियाकला वार्ड क्रमांक 54 में पीलिया के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 7 से 12 नवंबर के बीच 5 से 10 वर्ष की उम्र के 9 बच्चे पीलिया से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 8 बच्चों का इलाज घर पर ही चल रहा है, जबकि एक बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य और स्थिर है। प्रारंभिक जांच में नगर निगम के नल से आपूर्ति होने वाले दूषित पानी को संक्रमण की संभावित वजह माना जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और संबंधित नोडल अधिकारियों की टीम ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान इलाके के 286 घरों का सर्वे किया गया, ताकि संक्रमण की स्थिति और अन्य संभावित मरीजों का पता लगाया जा सके। पानी की



गुणवत्ता की जांच के लिए चार अलग-अलग स्थानों से पानी के सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमित बच्चों के ब्लड सैंपल भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही संक्रमण के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। नागरिकों से पानी उबालकर पीने, घरों में साफ-सफाई रखने और खानपान में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में प्रभावित क्षेत्र में सर्वे और जांच की प्रक्रिया जारी है।

कम उत्पादन होने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी आदान सहायता

प्रति एकड़ 13,839 का निर्णय किसान हित में महत्वपूर्ण पहलः मंत्री गजेन्द्र यादव



यश भारत



दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में पात्र धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री एवं दुर्ग विधायक गजेन्द्र यादव ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के किसानों के हित में महत्वपूर्ण और राहतकारी पहल बताया है।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की मेहनत, उनकी जरूरतों और कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब किसान यदि कम उत्पादन के कारण प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें सत्यापित धान के रकबे के अनुसार पूरी निर्धारित आदान सहायता राशि मिलेगी।

उन्होंने कहा कि पहले कम उत्पादन होने की स्थिति में किसानों को निर्धारित मात्रा के अनुपात में ही सहायता मिल पाती थी। अब सरकार ने किसानों को राहत देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि कम उपज के कारण उन्हें आर्थिक सहायता से वंचित न होना पड़े। यह निर्णय विशेषकर उन किसानों के लिए लाभकारी होगा, जहां प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण धान का उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है।

मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की किसान कल्याण की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। धान खरीदी के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का यह निर्णय किसानों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इलाज के दौरान युवक की मौत, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप स्वास्थ्य विभाग ने गठित की जांच टीम

यश भारत



दुर्ग। जिले के उतई स्थित आस्था हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। मृतक लोमेश ठाकुर के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) दुर्ग से शिकायत की थी। शिकायत के बाद सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी ने जांच टीम गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिसके चलते लोमेश की मौत हुई। वहीं अस्पताल की डॉक्टर डॉ. तृप्ति तिवारी ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि युवक पिछले तीन दिनों से लगातार शराब का सेवन कर रहा था। अस्पताल लाए जाने के दौरान उसकी नाड़ी की गति तेज और ब्लड प्रेशर काफी कम था। जांच में आंत फटने की स्थिति सामने आई थी, जिसके चलते तत्काल ऑपरेशन करना जरूरी था।

डॉ. तिवारी के मुताबिक, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक परिजन ऑपरेशन कराने का निर्णय नहीं ले सके। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीज की गंभीर स्थिति के बारे में बार-बार जानकारी दी गई और दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाने का विकल्प भी बताया गया, लेकिन परिजन इसके लिए भी तैयार नहीं हुए। शाम करीब 7 बजे ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया गया। इसके बाद मरीज को ड्रेसिंग रूम ले जाने के लिए व्हीलचेयर पर बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर का दावा है कि मरीज का एक दोस्त, जो नशे में था, उसे पैदल चलाने की जिद करने लगा और जबरन पैदल चलने के लिए मजबूर किया।

डॉक्टर के अनुसार, ड्रेसिंग रूम पहुंचते ही मरीज अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद परिजनों ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। अस्पताल की ओर से ऑक्सीजन लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन डॉक्टर का आरोप है कि मरीज के दोस्तों ने इसका विरोध किया। इस दौरान परिजन डॉक्टरों से बहस करते रहे और मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि ऑपरेशन के निर्णय में हुई देरी के कारण मरीज की स्थिति गंभीर होती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई।

फिलहाल मामले में अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के आरोपों के बीच वास्तविक स्थिति जांच का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की गठित टीम अस्पताल में किए गए इलाज, चिकित्सकीय दस्तावेजों और परिजनों की शिकायत की जांच करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अस्पताल प्रबंधन की भूमिका और आगे की कार्रवाई तय होगी।

किसानों और आमजन के काम समय पर हों, राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी-संभागायुक्त दुग्गा

पटना और बैकुंठपुर तहसीलों का किया निरीक्षण; धान खरीदी, प्रमाण पत्र और बंटांकन सीमांकन के कार्यों की समीक्षा

आरबीसी 6-4 के प्रकरणों में संवेदनशीलता बरतें, प्रभावित परिवारों को समय पर मिले आर्थिक सहायता

कोरिया। सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेंद्र कुमार दुग्गा ने आज जिले के पटना एवं बैकुंठपुर तहसील कार्यालयों का निरीक्षण कर राजस्व संबंधी कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा किसानों और आमजन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित संबंधित एसडीएम एवं तहसीलदार उपस्थित रहे।

संभागायुक्त ने कहा कि तहसील कार्यालयों में किसान, विद्यार्थी और आम नागरिक विभिन्न आवश्यकताओं को लेकर पहुंचते हैं। उनके आवेदनों पर समयबद्ध एवं नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राजस्व कार्यों में तेजी के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

धान खरीदी से जुड़े राजस्व कार्यों को दें प्राथमिकता

धान खरीदी की तैयारियों के संदर्भ में श्री दुग्गा ने किसानों से जुड़े राजस्व कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने



पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों से समन्वय कर भूमि एवं राजस्व अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं का समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए, जिससे किसानों को धान विक्रय में अनावश्यक परेशानी न हो।

संभागायुक्त ने जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र बनाने के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये प्रमाण पत्र विद्यार्थियों की पढ़ाई, छात्रवृत्ति, प्रवेश तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। आवेदनों की समय पर जांच कर पात्र आवेदकों को निर्धारित समयसीमा में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएं। आवेदन में कोई कमी होने पर आवेदक को स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि वह उसे पूरा कर सके।

श्री दुग्गा ने राजस्व अभिलेखों की नकल प्राप्त करने के लिए आए आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों एवं अन्य आवेदकों को आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध कराए जाएं।

उन्होंने बंटांकन एवं सीमांकन के लंबित प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मैदानी जांच और आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी करने को कहा। साथ ही लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने तथा लंबे समय से लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त ने तहसीलदारों को आरबीसी 6-4 (राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6, कंडिका 4) के प्रकरण समय पर पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि ये मामले मानवीय संवेदना और प्रभावित परिवारों के आर्थिक संबल से जुड़े हैं। इनके निराकरण में देरी से परिवारों की कठिनाइयां और मानसिक परेशानी बढ़ती है।

उन्होंने कहा कि कार्य की अधिकता के बीच भी ऐसे संवेदनशील प्रकरणों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेते हुए आवश्यक जांच एवं प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें, ताकि पात्र परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। संभागायुक्त ने कहा कि राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली सहज, पारदर्शी और जनहित के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। अधिकारियों की सक्रियता का परिणाम आमजन को समय पर सेवाएं मिलने के रूप में दिखाई देना चाहिए।

आदिवासी महिलाओं की अस्मिता, स्वाभिमान और सशक्तिकरण का नया अध्याय

यश भारत

रायपुर। भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत के संरक्षण में जनजातीय समाज का योगदान अविस्मरणीय है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध 'उलगुलान' का शंखनाद करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाया जा रहा जनजातीय गौरव दिवस हमें अपने महान नायकों के साहस, स्वाभिमान और बलिदान का स्मरण कराता है। शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुण्डाधूर, शहीद गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष हमारी साझा विरासत है। इस पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समाज के गौरव और योगदान को राष्ट्रीय पहचान मिली है। वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के बाद से जनजातीय अंचलों के विकास को नई गति मिली है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के संवेदनशील नेतृत्व में 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का संकल्प दूरस्थ वनांचलों तक पहुंच रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।

जनजातीय समाज की मजबूती में माताओं और बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से हम उनके सम्मान, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। महतारी वंदन योजना से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। यह आर्थिक सहायता उन्हें परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों में अपने स्तर पर निर्णय लेने का संबल देती है। जनजातीय महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मविश्वास को मजबूत करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

गरीब और वंचित परिवारों की बेटियों के विवाह का आर्थिक भार कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2 हजार 72 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 हितग्राही अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां हैं। यह पहल परिवारों को सहयोग देने के साथ बेटियों के सम्मान और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। माताओं और बच्चों के पोषण तथा प्रारंभिक देखभाल पर भी विशेष ध्यान



दिया जा रहा है। पीएम-जनमन अभियान के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बसाहटों में 191 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और सभी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इनके माध्यम से वनांचलों में बच्चों को पोषण और प्रारंभिक शिक्षा तथा गर्भवती माताओं को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल 'प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान' (पीएम-जनमन) से छत्तीसगढ़ की पांच विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों-बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर के गांवों और बसाहटों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 1 हजार 545 ग्रामों और 2 हजार 365 बसाहटों का संतृप्तिमूलक विकास किया जा रहा है।

अब तक 24 हजार 218 पक्के आवास पूरे हो चुके हैं और 1 हजार 833 किलोमीटर सड़कें बनाई जा चुकी हैं। 7 हजार 349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। इसके साथ ही 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 16 वनधन विकास केंद्र संचालित हैं। इन प्रयासों से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और स्थानीय आजीविका के अवसरों को मजबूती मिल रही है।

इसी दिशा में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। अभियान के अंतर्गत 733.258 करोड़ रूपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें छात्रावास और आश्रम, पांच जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (ञ्जस्रस्रष्ठह्य) तथा एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए 'सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस' की स्थापना जैसे कार्य शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की सुविधाओं को जनजातीय समुदायों के निकट पहुंचाना है। जनजातीय कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता बजट आवंटन में भी दिखाई देती है। आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रूपये था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रूपये किया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि है। वनाधिकारों की मान्यता के माध्यम से समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को भी संरक्षण मिला है। छत्तीसगढ़ में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। ये अधिकार जल, जंगल और जमीन से जुड़े जनजातीय समुदायों के पारंपरिक संबंध और आजीविका को मजबूत करते हैं।

जनजातीय गौरव दिवस केवल अतीत के गौरव को स्मरण करने का अवसर नहीं, बल्कि उस विरासत को सम्मान देते हुए बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प भी है। हमारी प्राथमिकता है कि जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े जीवन मूल्यों को सहेजते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के अवसर हर गांव तक पहुंचें। आइए, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय समाज के सभी महान नायकों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।

जय जोहार! जय छत्तीसगढ़!

भूपेश बघेल मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं : रंजना साहू



अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए बघेल कर रहे हैं अनर्गल प्रलाप

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि बघेल इन दिनों 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ व पराक्रम और प्रदेश की जनता-जनार्दन के असीम स्नेह व विश्वास ने जिस तरह भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल के कुशासन को 2023 में सत्ता से उखाड़ फेंका, उससे न केवल बघेल, अपितु पूरा कांग्रेस नेतृत्व सदमे और सन्निपात के दौर से गुजर रहा है। इसी हताशा में वे इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप की नियति का शिकार हो गए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती साहू ने कहा कि आज भूपेश बघेल की न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति में, बल्कि स्वयं कांग्रेस पार्टी के भीतर भी कोई राजनीतिक प्रासंगिकता शेष नहीं रह गई है। वे अपनी ही पार्टी में पूरी तरह अलग-थलग पड़ गए हैं। श्रीमती साहू ने तंज कसते हुए कहा कि राजनीतिक हाशिये पर जा चुके श्री बघेल इस तरह की बयानबाजी करके केवल अपने डूबते हुए सियासी वजूद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर निशाना साधते हुए श्रीमती साहू ने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी की दिल्ली रैली में छत्तीसगढ़ के अधिकांश नेताओं के न पहुँचने पर प्रदेश नेतृत्व को अपने ही नेताओं को नोटिस देने का मन बनाना पड़ रहा हो, उस बिखरी हुई पार्टी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे हालात में कांग्रेस के 'वन-वे लीडर' बन चुके भूपेश बघेल यदि भाजपा के एक इनोवा कार में सिमट जाने की हास्यास्पद कल्पना करते हैं, तो उन्हें यह खुशफहमी मुबारक हो। ?श्रीमती साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के पिछले कार्यकाल के भ्रष्टाचार और कुशासन को भूली नहीं है, इसलिए बघेल को मुंगेरीलाल के सपने देखने के बजाय अपनी पार्टी के भीतर बचे-खुचे जनाधार की चिंता करनी चाहिए।

डिलीवरी बॉय को बाइक से टक्कर मारकर लूटा, 5 हजार नकद और सोने की अंगूठी लेकर हुए फरार

डुमर तालाब के पास वारदात को दिया अंजाम, CCTV फुटेज की मदद से आमानाका पुलिस ने पकड़ा



रायपुर। राजधानी में डिलीवरी बॉय को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पहले बाइक से टक्कर मारकर डिलीवरी बॉय को सड़क पर गिराया और फिर उसके साथ मारपीट कर नकदी और सोने की अंगूठी लूट ली। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली है।

मामला आमानाका थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित हबीब खान स्विगी इंस्टामार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता है। 10 नवंबर को वह अपनी एक्टिवा से महोबा बाजार से सरोना की ओर पार्सल पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान डुमर तालाब के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसकी एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। इसके बाद आरोपियों ने उससे पैसों की मांग शुरू कर दी। पीड़ित के विरोध करने पर एक अन्य व्यक्ति भी मौके पर पहुंच गया। तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और जेब में रखे पर्स से 5 हजार रुपये नकद तथा हाथ में पहनी सोने की अंगूठी लूटकर फरार हो गए।

घटना की शिकायत मिलने पर आमानाका पुलिस ने अपराध क्रमांक 376/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(6) और 3(5) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और आमानाका थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। घटनास्थल और आसपास लगे ष्टष्टञ्जङ्क कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने दुष्यंत साहू और शुभांशु नागवंशी उर्फ शिब्बू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त की है। दोनों आरोपी आमानाका थाना क्षेत्र के डुमर तालाब के पास के निवासी बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को ओ.एन.ओ.एस के माध्यम से 13 हजार शोध पत्रिकाओं तक मिली पहुँच

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न



रायपुर। इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (नई दिल्ली) और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन आज कृषि महाविद्यालय, रायपुर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल के उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धता तथा इसके प्रभावी उपयोग के संबंध में प्रतिभागियों को जागरूक करना था। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई इस पहल के माध्यम से केंद्रीकृत सदस्यता व्यवस्था के अंतर्गत देशभर के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को शोध प्रकाशनों एवं अकादमिक पत्रिकाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना प्रारंभ की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को इसे स्वीकृति प्रदान की तथा इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ हुआ। योजना के प्रथम चरण (2025-2027) के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत देश के पात्र उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों को 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं तक एकीकृत डिजिटल पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, यू.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जैसे कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं शोधार्थियों को कृषि विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, फसल सुधार, पादप संरक्षण, जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय शोध एवं वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे स्नातकोत्तर एवं पीएच.डी. शोधार्थियों के शोध कार्य की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग एवं बहुविषयक अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में ओ.एन.ओ.एस योजना के प्रभारी डॉ. एस.के.त्रिपाठी ने इस योजना का महत्व बताते हुए कहा कि ओ.एन.ओ.एस योजना कृषि अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक ज्ञान और नवीनतम वैज्ञानिक शोध तक पहुंच उपलब्ध कराने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है। इसका प्रभावी उपयोग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता, नवाचार, अंतरराष्ट्रीय अकादमिक सहयोग तथा कृषि तकनीकी विकास को नई दिशा प्रदान कर सकता है। विश्वविद्यालय में ओ.एन.ओ.एसयोजना के अधिकतम उपयोग के लिए इसके पंजीकरण एवं क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में नेहरू पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. उदय कुमार वट्टी ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रतिपादित की।

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को ओ.एन.ओ.एस की कार्यप्रणाली, इसकी पहुंच एवं उपयोग की सुविधाओं, विभिन्न विशेषताओं के व्यावहारिक उपयोग तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों की जानकारी दी गई।

जनजातीय समाज का स्वाभिमान, भूमि अधिकारों की सुरक्षा और युवाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता: टंक राम वर्मा



रायपुर। जनजातीय गौरव दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, स्वाभिमान, संघर्ष और बलिदान की गौरवशाली विरासत को नमन करने का पावन अवसर है। यह दिवस हमें उन महान जननायकों की याद दिलाता है, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता तथा मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासियों, विशेषकर जनजातीय समाज के भाई-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

भगवान बिरसा मुंडा का जीवन साहस, संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान की अद्भुत गाथा है। उन्होंने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए समाज को एकता और अधिकारों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ की पावन धरती भी शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे महान जननायकों की कर्मभूमि रही है। इन वीर सपूतों का बलिदान हमारी ऐतिहासिक चेतना और राष्ट्रीय गौरव का अभिन्न हिस्सा है।

छत्तीसगढ़ की आत्मा उसकी जनजातीय संस्कृति में बसती है। यहां के लोकगीतों में प्रकृति का संगीत है, लोकनृत्यों में जीवन का उल्लास है और परंपराओं में सामूहिकता, सहअस्तित्व तथा सामाजिक समरसता का संदेश है। बस्तर से सरगुजा तक फैली जनजातीय संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। इस विरासत को सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय एवं दूरस्थ वनांचलों में निवासरत परिवारों को शासन की सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और विकास के अवसरों का समुचित लाभ मिले।

जनजातीय समाज का अपनी भूमि, प्रकृति और परंपराओं से गहरा संबंध है। भूमि केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान, पारिवारिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार भी है। इसी भावना के अनुरूप राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण, राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और नागरिकों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं।

प्रदेश में भुइयाँ पोर्टल, भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भुइयाँ व्हाट्सऐप चौटबॉट जैसी सुविधाओं से नागरिकों के लिए राजस्व संबंधी जानकारी प्राप्त करना और अधिक सुगम हुआ है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय बच्चों की शिक्षा को नई दिशा, नियद नेल्ला नार योजना से बंद पड़े 421 स्कूल पुनः प्रारंभ

16 लाख से अधिक आदिवासी विद्यार्थी विद्यालयों में पा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाएं धरातल पर सार्थक परिणाम दे रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनजातीय बहुल और सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा की पहुँच को सुदृढ़ करने, शाला त्यागी दर (ड्रॉपआउट रेट) को न्यूनतम स्तर पर लाने और विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शैक्षणिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

वर्तमान में राज्य के कक्षा ेज से 12जी तक के विद्यालयों में कुल 51 लाख 56 हजार 691 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इनमें से 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी (31.27:) जनजातीय वर्ग से आते हैं। केवल शासकीय विद्यालयों की बात करें तो वहाँ अध्ययनरत आदिवासी विद्यार्थियों की संख्या 13 लाख 28 हजार 816 है, जो राज्य में जनजातीय शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और विश्वास को दर्शाती है।

राज्य के बस्तर संभाग और अति-संवेदनशील जिलों जैसे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा में शिक्षा का ढांचा मजबूत करने में नियद नेल्लनार योजना वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत पूर्व में बंद पड़े 458 विद्यालयों में से 421 बंद स्कूलों को 30 अक्टूबर 2026 तक पुनः सफलतापूर्वक प्रारंभ कर लिया गया है। इससे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों के बच्चों को दोबारा मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिला है।

राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तिछात्रवृत्ति योजना से लाभानिवत किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 54 हजार 225 छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सरस्वती साइकिल योजना से लाभान्वित की गई है। निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को गणवेश तथा 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का विरित कर लाभ पहुंचाया गया। बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा जैसे जिलों में 60 पोटा केबिन आवासीय विद्यालय तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (चत्तब्बङ्क) संचालित हैं।

पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास (25 छात्रावास 50-सीटर और 15 छात्रावास 100-सीटर) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 42 नए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।

भाषा संबंधी कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी और कुडुख जैसी स्थानीय बोली-भाषाओं में शिक्षण सामग्री विकसित की गई है। इसके माध्यम से 13 हजार 35 शासकीय प्राथमिक स्कूलों के लगभग 3.60 लाख बच्चों को उनकी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

डॉ. ममता साहू की अध्यक्षता में छह जिलों के अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

महिलाओं और बच्चों के अधिकार, सुरक्षा तथा विधिक प्रावधानों पर धमतरी में आयोजित हुआ एक दिवसीय जागरूकता कार्य म

सखी वन स्टॉप सेंटर, पुलिस, संरक्षण अधिकारियों और विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि हुए शामिल



छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने की। प्रशिक्षण में धमतरी के साथ रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर और बालोद जिले के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

धमतरी के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सुबह 10 बजे से आयोजित कार्यक्रम में सखी वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर, केस वर्कर और मेडिकल पर्सन, संरक्षण अधिकारी, पुलिस विभाग के वूमेन हेल्प डेस्क के प्रतिनिधि तथा विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों में कार्यरत विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को संबंधित कानूनों की जानकारी देना और उनके कार्यों में आवश्यक समन्वय के विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना था।

कार्यक्रम में आयोग की सदस्य श्रीमती सरला कोसरीया और सुश्री दीपिका सोरी, कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, आयोग के सचिव श्री रमेश साहू, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन देवहारी, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रीति दुर्गम, अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती कल्पना ध्रुव तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री महेश मरकाम उपस्थित थे।

प्रशिक्षण सत्र में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, धमतरी श्री आनंद पाठक ने बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम (जेजे एक्ट) और पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की। इसके बाद श्री धनंजय तिवारी ने महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कानूनों की तकनीकी जानकारी देते हुए भारतीय न्याय संहिता, घरेलू हिंसा से संबंधित कानून और महिलाओं के संरक्षण के लिए लागू अन्य विधिक प्रावधानों के बारे में बताया।

यूसीसी की उच्चस्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न



रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में छत्तीसगढ़ समान नागरिक संहिता की उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में समान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम. के. राऊत, शत्रुघ्न सिंह एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह तथा समिति के सचिव श्याम धावड़े उपस्थित रहे।

चिंतन-मनन

विकास की कसौटी

भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आर्थिक विकास के आंकड़े, बढ़ता बुनियादी ढांचा, एक्सप्रेसवे, आधुनिक रेल नेटवर्क, डिजिटल सेवाएं और औद्योगिक विस्तार देश की बदलती तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। विकसित भारत का सपना भी इसी प्रगति की मजबूत नींव पर खड़ा है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के बीच एक सवाल लगातार सामने आता है कि क्या आर्थिक विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक समान रूप से पहुंच रहा है? क्या आम आदमी का जीवन उतना ही आसान और सुरक्षित हुआ है, जितनी तेजी से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यह निश्चित रूप से उत्साहजनक उपलब्धि है। आर्थिक विकास से निवेश, उत्पादन, व्यापार और सरकारी राजस्व के अवसर बढ़ते हैं। इसके लिए सरकार की नीतियों, उद्योगों की भूमिका और बुनियादी ढांचे के विस्तार का महत्व भी स्वीकार करना होगा। हालांकि, जीडीपी की वृद्धि अपने आप में आम नागरिक की आर्थिक खुशहाली का पूरा प्रमाण नहीं हो सकती। विकास का वास्तविक अर्थ तब सामने आता है, जब उसका लाभ किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, नौकरीपेशा व्यक्ति, युवा और मध्यमवर्गीय परिवार तक पहुंचे। आज आम परिवार की सबसे बड़ी चिंता महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। एक सामान्य परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई, मकान के किराये, राशन, बिजली और चिकित्सा पर खर्च करता है। निजी अस्पतालों में इलाज और निजी शिक्षण संस्थानों की फीस लगातार बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है। सरकारी अस्पतालों और विद्यालयों पर भी आबादी का दबाव है। ऐसे में आर्थिक विकास के आंकड़ों के साथ यह देखना भी जरूरी है कि आम आदमी की बचत बढ़ रही है या उसकी आय का अधिकांश हिस्सा जरूरी खर्चों में समाप्त हो रहा है। देश के सामने रोजगार का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। युवाओं के पास डिग्रियां हैं, तकनीकी शिक्षा है और आगे बढ़ने की आकांक्षा भी है, लेकिन उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप स्थायी रोजगार मिलना अभी भी बड़ी चुनौती है। केवल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना पर्याप्त नहीं है। उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, कृषि आधारित व्यवसायों और सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने होंगे। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के साथ छोटे उद्यमियों को आसान ऋण, बाजार और तकनीकी सहायता उपलब्ध करानी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को विकास की प्राथमिकता बनाना भी आवश्यक है। सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएं और डिजिटल सुविधाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता का अंतर कम करना होगा। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त चिकित्सक, दवाएं, जांच सुविधाएं और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा इतनी सुलभ हो कि किसी परिवार को बीमारी के कारण अपनी वर्षों की बचत या संपत्ति गंवानी न पड़े। विकास का एक महत्वपूर्ण पक्ष ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी है। किसान की आय, कृषि की लागत, सिंचाई, फसल का उचित मूल्य और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए बिना समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा और कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी विकास के मूल्यांकन का हिस्सा होनी चाहिए। सरकार के लिए आवश्यक है कि बजट और नीतियां बनाते समय बड़े निवेश और विकास दर को प्राथमिकता के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ पेयजल, सस्ती आवास व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। योजनाओं की सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि उनका लाभ कितने लोगों तक पहुंचा और उनके जीवन में कितना वास्तविक बदलाव आया। इसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थानीय स्तर पर नियमित निगरानी जरूरी है। विकसित भारत का सपना किसी एक सरकार, संस्था या वर्ग का लक्ष्य नहीं बल्कि पूरे देश की सामूहिक आकांक्षा है। आर्थिक शक्ति और आधुनिक तकनीक इस लक्ष्य तक पहुंचने के महत्वपूर्ण साधन हैं, लेकिन अंतिम मंजिल नागरिकों की खुशहाली है। देश तभी वास्तव में विकसित कहलाएगा, जब किसी गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए संघर्ष न करना पड़े, किसी परिवार को इलाज के अभाव में परेशानी न झेलनी पड़े और किसी युवा को रोजगार के लिए अपनी योग्यता से समझौता न करना पड़े। जीडीपी देश की आर्थिक प्रगति बताती है, लेकिन आम आदमी के चेहरे की संतुष्टि ही विकास की वास्तविक सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

कड़वे वचन



किसी ने पूछाः मंदिर जाते हैं तो पहले घंटी क्यों बजाते हैं? मैंने प्रतिप्रश्न कियाः फोन आता है तो पहले घंटी क्यों बजती है? फोन की घंटी इशारा है कि किसी ने पुकारा है और मंदिर की घंटी भी इशारा है कि प्रभु तेरा ही सहारा है। मंदिर की घंटी के संग मन मंदिर की घंटी भी बजनी चाहिए। कहें- हे प्रभु मेरा नाथ तू है, दुनिया में हूं अकेला, पर मरे साथ तू है।

आज का राशिफल



ज्योतिषाचार्य पंडित लोकेश व्यास

पंचांगः-14 नवम्बर, 2026
दिन-शनिवार, अश्विन शुक्ल 10
विक्रम संवत 2083

मेष — चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ
बिना मांगे सलाह देने से बचे लेनदेन के मामले में सतर्क रहें देवी पार्वती का पूजन करें

वृष — इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो
घर के बाहर वाद-विवाद से दूर रहे मन की इच्छा पूर्ण होगी चांदी की गिलास में पानी पिए

मिथुन — का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह
उधार लेने व देने से बचें विद्यार्थियों के लिए समय ठीक नहीं है मन में भटकाव रहेगा वट वृक्ष का पूजन करें

कर्क — ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो
ंरुका हुआ पुराना काम बन सकता है परिवार के किसी सदस्य के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ओम विधि रूपाय नमः का जाप करें

सिंह — मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे
वरिष्ठ ओं का मार्गदर्शन मिलेगा अपने ऊपर फोकस बनाए रखें भगवान शिव को जल चढ़ाएं

कन्या — ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो
कारोबारी कार्य में मन लगेगा लाभ के अवसर मिलेंगे लालच में ना फंसे ओम नमः पार्वती पति यह नमः का जाप करें

तुला — रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते
धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे पारिवारिक चिंता रहेगी शुक्र ग्रह का पूजन करें

वृश्चिक — ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे
मन प्रफुल्लित रहेगा तेज ड्राइविंग से बचे हनुमानजी के दर्शन करे

धनु — ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे
आज मनमाफिक काम होंगे पुरानी स्मृतियों का मन पर कब्जा रहेगा ब्राह्मणों को दान दे

मकर — भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी
घूमने फिरने की योजना साकार होगी मनचाहे लोगों का साथ मिलेगा हाइपर होने से बचे शनि का पूजन करें

कुंभ — गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा
दिन तनाव भरा कठिन रहेगा शाम की बात मन प्रसन्न रहेगा पीपल के वृक्ष में दिया लगाएं

मीन — दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची
लोगों के मैसेज पढ़ कर मन प्रसन्न होगा तारीफ होगी लालच में ना फंसे गुरुओं की सेवा करें

14 नवंबर बाल दिवसः अधिकार, संस्कार और सुनहरे भविष्य का संकल्प

बच्चों के मौलिक अधिकारों, उनकी शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के प्रति समाज को जागरूक करने तथा उन्हें सुरक्षित एवं रचनात्मक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का भी अवसर है, जिन्हें बच्चे स्नेहपूर्वक चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। वास्तव में, बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाकर उनके अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें अच्छी शिक्षा एवं समुचित पोषण उपलब्ध कराना और उनके संपूर्ण विकास के लिए सुरक्षित तथा खुशहाल वातावरण तैयार करना है, ताकि वे देश के बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।गौरतलब है कि वर्ष 1889 में जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू की वर्ष 2026 में 137वीं जयंती है। वर्ष 1964 में उनके निधन के बाद से 14 नवंबर को बाल दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई और इस वर्ष इसका 63वाँ आयोजन है। वहीं, प्रतिवर्ष 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस (विश्व बाल दिवस) मनाया जाता है। इस अवसर पर यूनिसेफ बच्चों के अधिकारों, कल्याण और उनके बेहतर भविष्य से जुड़े मुद्दों को वैश्विक स्तर पर प्रमुखता देता है तथा प्रतिवर्ष इस दिशा में एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

आज हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के तेज रफ्तार युग में जी रहे हैं। ऐसे में बाल दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं, बल्कि बच्चों के बदलते बचपन और उनके सामने उभरती नई चुनौतियों पर गंभीर चिंतन करने का अवसर भी बन गया है। कहना गलत नहीं होगा कि आज के बच्चे मिट्टी के खिलौनों और दादी-नानी की कहानियों की दुनिया से निकलकर स्मार्टफोन, टैबलेट और एल्गोरिदम की आभासी दुनिया में बड़े हो रहे हैं। जहाँ एक ओर एआई ने व्यक्तिगत शिक्षा, त्वरित ज्ञान और दिव्यांग बच्चों के लिए सीखने के नए द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर तैयारशुदा और पलभर में मिलने वाले उत्तरों की सुविधा ने उनकी मौलिक कल्पनाशीलता, जिज्ञासा और स्वयं प्रयास करके सीखने की प्रवृत्ति के सामने नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर दी हैं।ऐसे में इस बाल दिवस की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि हम बच्चों को तकनीक का गुलाम बनाने के बजाय उसका विवेकशील उपयोगकर्ता बनाएं। उनके हाथों में स्मार्ट उपकरण थमाने के साथ-साथ उनके भीतर मानवीय संवेदनाओं, खेल के मैदान की ऊर्जा और प्रकृति से जुड़ाव की लौ भी जीवित रखें। तकनीक उनके ज्ञान और विकास का साधन बने, न कि उनके स्वाभाविक बचपन और रचनात्मकता पर हावी होने का माध्यम।

वास्तव में, बाल दिवस आत्ममंथन करने का दिन है कि हम अपने बच्चों को कैसा बचपन और कैसा भविष्य दे रहे हैं। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है और प्रतिस्पर्धा का दबाव कम उम्र में ही उनके मन-मस्तिष्क पर हावी होने लगा है, तब बच्चों के विकास को केवल अच्छे अंक और बेहतर करियर तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। सच तो यह है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे पहले उन्हें सुरक्षित, स्नेहपूर्ण और भयमुक्त वातावरण देना जरूरी है। हमें यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि बच्चे का व्यक्तित्व केवल स्कूल की चारदीवारी में नहीं बनता, बल्कि परिवार, समाज, मित्रों और परिवेश से भी आकार लेता है। माता-पिता



का समय, उनका व्यवहार, आपसी संवाद और दिए गए संस्कार बच्चे के मानसिक एवं भावनात्मक विकास की बुनियाद होते हैं। अतः आज जरूरत इस बात की है कि माता-पिता बच्चों पर अपनी अपेक्षाएँ थोपने के बजाय उनकी रुचियों, क्षमताओं और भावनाओं को समझें तथा उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने के पर्याप्त अवसर दें।

स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें तो, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात् शिक्षा भीतर छिपी श्रेष्ठ संभावनाओं को बाहर लाने का माध्यम है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना और नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील तथा जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी है।सच तो यह है कि बच्चों को सवाल पूछने, तर्क करने, नई चीजें सीखने और अपनी कल्पनाशक्ति को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। रटने और अंकों की अंधी दौड़ से बाहर निकलकर शिक्षा को रचनात्मकता, व्यावहारिक ज्ञान और जीवन-मूल्यों से जोड़ना समय की मांग है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा करना ही नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करना, सही-गलत में अंतर समझना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी सिखाए।

आज के डिजिटल दौर में बच्चों को मोबाइल और आभासी दुनिया तक सीमित रखने के बजाय मैदान, पुस्तकालय, प्रकृति और वास्तविक सामाजिक जीवन से जोड़ना भी बेहद जरूरी है। बच्चों के विकास में खेलकूद, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या की अहम भूमिका होती है। खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व, धैर्य और हार को स्वीकार करने की सीख भी देते हैं। इसी तरह संगीत, साहित्य, कला और अन्य रचनात्मक गतिविधियाँ बच्चों की संवेदनशीलता, कल्पनाशक्ति और अभिव्यक्ति क्षमता को समृद्ध करती हैं।इसके साथ ही,आज बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक है। हमें समझना होगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। किसी की रुचि विज्ञान में होती है तो किसी की साहित्य, खेल, संगीत या कला में। किसी की सीखने की गति तेज होती है तो किसी को थोड़ा अधिक समय चाहिए। ऐसे में बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना, छोटी-छोटी गलतियों पर उन्हें अपमानित करना और असफलता को अपराध की तरह देखना उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। बच्चों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक अवसर है।बच्चों में संवेदनशीलता, समानता, पर्यावरण संरक्षण, बुजुर्गों के प्रति सम्मान, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे जीवन-मूल्यों का विकास भी जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी केवल उन्हें सफल व्यक्ति बनाना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना भी है।

बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात तब तक अधूरी है, जब तक समाज उनके मौलिक अधिकारों और सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। बाल श्रम, बाल विवाह, शोषण, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा से वंचित बच्चों की समस्याओं के प्रति समाज को गंभीर होना होगा। प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण और सुरक्षित वातावरण मिलना उसका मौलिक अधिकार है, किसी का उपकार नहीं।यह भी जरूरी है कि परिवार, विद्यालय, समाज और सरकार मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करें, जहाँ बच्चे बिना किसी भय और दबाव के अपनी प्रतिभा को निखार सकें। उनकी बात सुनी जाए, उनकी जिज्ञासाओं को प्रोत्साहित किया जाए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझा जाए। बच्चों के अधिकारों की रक्षा केवल कानूनों और सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक संवेदनशीलता और सामूहिक जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है।

बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चे केवल देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी हैं। यह दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस सपने की याद दिलाता है, जिसमें हर बच्चा शिक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित हो। यह अवसर हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें तथा समाज उन्हें बाल श्रम, शोषण और अन्य सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए सजग रहे।बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार, प्रेम, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्य देना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आज के बच्चों को उचित मार्गदर्शन, शिक्षा, पोषण और सुरक्षित वातावरण मिलेगा, तो कल का भारत स्वतः ही सशक्त और समृद्ध बनेगा। हर बच्चे को खिलखिलाने, खेलने, अपनी जिज्ञासाओं को उड़ान देने और सपनों को साकार करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

अंततः, बाल दिवस की सच्ची सार्थकता केवल समारोहों, भाषणों और उपहारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हमारे व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारी में भी दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जिस समाज का बचपन सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ और खुशहाल होता है, उसी समाज का भविष्य उज्ज्वल होता है।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार)

स्त्री-प्रश्नों पर मूक होता समाज



सद्य विवाहिताओं की मृत्यु के मामले अक्सर मीडिया में चर्चित होते रहते हैं। इन मामलों में देखने में आता है कि इनकी शिकार बनने वाली महिलाएं लगातार ऐसी परिस्थितियों के बीच रहने को विवश होती हैं जिनमें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए जीना मुश्किल होता है। ऐसे मामले होने के बाद लड़कियों के घरवाले ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना सहित कई तरह के आरोप लगाते हैं और उन्हें मरने हेतु विवश करने या जान लेने का दोषी बताते हैं। इन सभी मामलों में सबसे कॉमन चीज यह है कि दहेज के लालच में या लड़की के परिवार से पैसे ऐंठने के चक्कर में ऐसी घटनाएं होती हैं। एक सामाजिक के रूप में दहेज देने वाला अपराध में, दहेज लेने वाले के बराबर ही हिस्सेदार होता है। लड़के के साथ ही लड़की के माता-पिता भी इसमें बराबर के दोषी होते हैं।

हमारे देश में दहेज हत्या की दर बहुत चिंताजनक है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 से लागू होने के बावजूद दहेज की वजह से होने वाली मृत्यु में वृद्धि इस प्रथा की लगातार बढ़त को दर्शाती है। दहेज के लिए अब भी बहुत महिलाओं को उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई सारी धाराएं हैं जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है लेकिन लम्बी जाँच प्रक्रिया की वजह से दोषियों को सजा मिलना दुर्लभ बना हुआ है। गवाही देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, जानते-बुझते सब अपना मुँह सी लेते हैं, ऐसे में सजा हो पाना सम्भव ही नहीं रह जाता। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में 2017 से 2022 के बीच प्रतिवर्ष औसतन 7,000 दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज की गईं। इन आँकड़ों में वे मामले शामिल नहीं होते जिनकी शिकायत नहीं की जाती। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1960 से 2008 तक ग्रामीण भारत में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि 95% शादियों में दहेज दिया गया था। यानी दहेज शादी का पर्याय हो चुका है।

दहेज के कारण बड़ी संख्या में होने वाली मौतों के बावजूद इस प्रथा का जारी रहना यह बताता है कि किसी सामाजिक समस्या को कानून बनाने मात्र से हल नहीं किया जा सकता। पिछले सालों में जिस तरह की भव्य शादियों का ट्रेंड हुआ है इससे यह कुप्रथा और भी बढ़ रही है। आत्मनिर्भर और शिक्षित लड़कियों की शादियों में भी खुलकर दहेज दिया जा रहा है। फिर कैसे यह सब रुकेगा जब समाज इसका भिन्न-भिन्न कारण बताकर महिमामंडन भी किए जा रहा है? यह प्रथा महिलाओं का वस्तुकरण करती है और पितृसत्तात्मक समाज में लैंगिक भेदभाव को बनाए रखने का माध्यम बनती है। दहेज का मुद्दा एक समाज के रूप में हमारे लिए विषय कभी नहीं बनता। इसमें सभी बराबर के भागीदार हैं। बेटी को दहेज दिया ही इसलिए जाता है कि उसका हिसाब बेटे की शादी में कर लिया जाएगा। दहेज किस तरह भारतीय पारिवारिक व्यवस्था में औरत को दोयम दर्जे पर बनाए रखने की पुख्ता व्यवस्था करता है इस पर कोई बहस नहीं होती। दहेज आर्थिक मसला नहीं है न केवल यह महिलाओं की शिक्षा या आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। यह पूरी व्यवस्था पैतृक सम्पत्ति से स्त्रियों को अलग करने और ताउम्र उन्हें पुरुष पर निर्भर रखने के लिए बनाई गई है। बेटी को सम्पत्ति के हक से महरूम करना और दहेज देना एक ही विषय के दो पहलू हैं। सम्पत्ति में हक नहीं देना पड़े इसीलिए दहेज दिया जाता है। इससे लड़कियाँ अहसान के रूप में उम्रभर भावनात्मक रूप से अपने परिवार पर निर्भर बनी रहती हैं। यह स्त्रियों को सदैव पराधीन बनाए रखने का तन्त्र है जिसे थोड़ा नुकसान झेलकर बनाए रखा जा सकता है। लड़की को दिए जाने वाले दहेज पर भी उसका अपना कोई हक नहीं होता वह अगले परिवार की सम्पत्ति है। बहुत सारा दहेज देकर विदा की हुई बेटी भी अपने घर में लौट नहीं सकती है। कोई समस्या होने पर अधिकांश लड़कियों का परिवार उन्हें अकेला छोड़ देता है और मृत्यु तक सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करता है। यह किस दर्जे की क्रूरता है? भारत में विवाह जहाँ एक सामाजिक मसला है वहीं विवाह में आने वाली समस्या को निजी माना गया है। इन दोनों के अन्तर्विरोध से भारतीय विवाह समस्याओं और संकटों के कुरुक्षेत्र बनने को बाध्य रहते हैं। सामाजिक दबाव के कारण परिवार दहेज मांगों को पूरा करना जहाँ अपनी मजबूरी मानते हैं वहीं इस वजह से होने वाली हिंसा का सामान्यीकरण किया जाता है। उत्पीड़न और हिंसा के अनेक मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती। समाज दहेज लोभी परिवारों का विरोध करने की बजाय इस गैरकानूनी प्रथा को प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से बढ़ावा देने का काम करता है। इस पूरी व्यवस्था में महिलाएं, भले ही वह माँ हो या सास पितृसत्ता की सबसे बड़ी पैरोकार बनकर खड़ी होती हैं। वे लड़की के होने को, उसकी सगाई टूटने को, शादी के बाद वापस घर लौटने को, अलग हो जाने को, लड़की के अस्मिता बोध को परिवार के लिए शर्म की तरह परिभाषित करती हैं। इस तरह लड़की के लिए स्वयं को बचाए रखने का कोई रास्ता समाज नहीं छोड़ता।प्रश्न यह है कि क्या इन मौतों से हमारे समाज को कोई फ़र्क पड़ता है, फ़र्क यदि पड़ता तो देशभर में रोज-रोज ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहती? लोग इन घटनाओं को सामाजिक व्यवस्था की उपज और अनिवार्य स्थिति नहीं मानते बल्कि दुर्घटनाओं की तरह मानते हैं। इससे उन्हें इन घटनाओं के पीछे की कहानी में अपनी भूमिका को विश्लेषित नहीं करना पड़ता, वे स्वयं अपराध-बोध से मुक्त रहते हैं। ऐसी मनोवृत्ति में ही इस तरह की घटनाएँ दोहराई जाती रहती हैं। इन्हें लड़की का दुर्भाग्य मानकर छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि ऐसे आरोप वाले परिवारों में लोग अपनी बेटियां देने में नहीं हिचकते, उन लड़कों का बहुत जल्द पुनर्विवाह हो जाता है। लड़की के मरने को समाज में समस्या के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि शर्म मानकर उसे दबा दिया जाता है। समाज की स्मृति में इन हत्याओं का कोई स्थान नहीं होता। दहेज के लिए होने वाली हत्याओं में कितनों को सजा होती हैं, वे केस फिर कुछ ले-देकर उठा लिए जाते हैं। जब तक समाज में महिलाओं को अपने निर्णय लेने की आजादी नहीं होगी तब तक ऐसे मामले होते ही रहेंगे। अकेले व्यक्ति से गलती हो सकती है लेकिन एक व्यवस्था जिस गलती को सालों-साल दोहराती है वह गलती नहीं सामाजिक निर्णय होता है। उन निर्णयों के बदलने हेतु सामाजिक संरचना को बदलना आवश्यक होता है। लड़कियों को ही अपने बारे में सोचना पड़ेगा। माता-पिता पर भावनात्मक निर्भरता ठीक है किन्तु अपनी कदर भी उन्हें करनी सीखनी चाहिए। उन्हें ही अपने लिए रास्ते बनाने होंगे, समाज उनके लिए सदैव से एक बंद रास्ता ही है।

(डॉ. मोनिका भाम्भू कलाना -यह लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

गर्म होती दुनिया में बढ़ते प्रदूषण से घुटती सांसें की चुनौती

आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन की उस कठोर सच्चाई का सामना कर रही है, जिसे कभी भविष्य की आशंका समझा जाता था। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, जंगलों की आग, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और असामान्य गर्मी अब असाधारण घटनाएं नहीं रह गई हैं। प्रकृति का संतुलन जिस तेजी से बिगड़ रहा है, उसने मानव सभ्यता के सामने अस्तित्व का गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 9 नवंबर 2026 को जारी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट 2026 रिपोर्ट इस संकट की भयावहता को वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ सामने रखती है। रिपोर्ट के अनुसार 2026 पिछले चार सबसे गर्म वर्षों में शामिल होने की राह पर है और जनवरी से सितंबर तक वैश्विक औसत तापमान 1850-1900 के पूर्व-औद्योगिक औसत से लगभग 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। 2015 से 2026 तक के सभी 12 वर्ष रिकॉर्ड के सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। यह आंकड़ा केवल तापमान की वृद्धि का आंकड़ा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के बढ़ते संकट का संकेत है। समुद्रों में जमा हो रही अतिरिक्त गर्मी, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र-स्तर, बढ़ता प्रदूषण और बदलता वर्षा चक्र आने वाले वर्षों की गंभीर चुनौतियों का संकेत दे रहे हैं। डब्ल्यूएमओ के अनुसार महासागर लगातार दसवें वर्ष रिकॉर्ड गर्मी की ओर हैं और 2026 में वैश्विक समुद्र-स्तर भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है।

इस वर्ष की स्थिति इसलिए भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि मजबूत अलनीनो विकसित हो रहा है। डब्ल्यूएमओ के अनुसार अगस्त से अलनीनो तेजी से मजबूत हुआ है और नवंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच इसकी तीव्रता असाधारण स्तर तक पहुंच सकती है। इसके कारण



2027 में अत्यधिक गर्मी, सूखा और भारी वर्षा जैसी चरम मौसमी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। अर्थात खतरा केवल आज का नहीं है। आने वाला वर्ष भी मानवता को प्रकृति के कठोर रूप का सामना करा सकता है। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन को केवल पर्यावरण मंत्रालयों या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का विषय मानना अब गंभीर भूल होगी। यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, जलस्रोत, आवास और सामाजिक स्थिरता से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। जलवायु संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसका सबसे बड़ा बोझ उन देशों और समुदायों पर पड़ रहा है, जिनका ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम रहा है। विकासशील और गरीब देशों के सामने एक साथ दो चुनौतियां हैं-विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना और जलवायु संकट से स्वयं को बचाना।

दशकों तक विकसित देशों ने औद्योगिक विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया। आज जब विकासशील देश आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, उनसे उत्सर्जन कम करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए जलवायु न्याय का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वैश्विक समुदाय वास्तव में समाधान चाहता है तो विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, अनुकूलन और आपदा-रोधी ढांचे के लिए पर्याप्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देनी होगी। इसी संदर्भ में तुर्किये के अंताल्या में चल रहा सीओपी-31 महत्वपूर्ण है। सम्मेलन 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है और इसका घोषित उद्देश्य जलवायु समाधानों के क्रियान्वयन तथा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को गति देना है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस बार दुनिया घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई करेगी?

पिछले अनेक जलवायु सम्मेलनों में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित हुए, लेकिन वास्तविक क्रियान्वयन की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। आज आवश्यकता नए संकल्पों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि पुराने संकल्पों को धरातल पर उतारने की है। विकसित देशों को वित्तीय दायित्वों को गंभीरता से लेना होगा। विकासशील देशों को तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाकर सौर, पवन, जल और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को तेजी से बढ़ाना होगा। शहरों की नियोजन व्यवस्था, सार्वजनिक परिवहन, भवन निर्माण, कृषि और उद्योग-हर क्षेत्र को जलवायु अनुकूल बनाना होगा। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है या नहीं। सवाल यह है कि हम इसके सामने कितनी जल्दी और कितनी ईमानदारी से खड़े होते हैं।

(लेखक - ललित गर्ग, लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

नहाय-खाय के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ, घरों से घाटों तक दिखने लगी रौनक

चार दिनों तक चलेगा सूर्यदेव की उपासना का पर्व



जबलपुर,यशभारत। लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। पर्व को लेकर शहर में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश मूल के परिवारों में खासा उत्साह है। घरों से लेकर पूजा स्थलों तक तैयारियां दिखाई देने लगी हैं। जबलपुर में छठ पूजा का विस्तार अब किसी एक घाट या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। नर्मदा के घाटों से लेकर शहर के अलग-अलग तालाबों और जलस्रोतों तक सूर्यदेव की आराधना की जा रही है।

छठ महासंघ के अनुसार शहर में करीब 18 स्थानों पर पूजा की व्यवस्था की गई है। छठ पर्व के पहले दिन नहाय-खाय पर व्रतियों ने स्नान और घरों की साफ-सफाई के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लिया। वहीं गौरीघाट, तिलवाराघाट, भटौली घाट और अधारताल तालाब सहित अन्य प्रमुख घाटों और जलस्रोतों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। पूजा की तैयारियों और पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। परिवार के सदस्य भी घाटों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं में जुटे रहे। शनिवार,14 नवंबर को पर्व के दूसरे दिन खरना होगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को पूजा-अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद निर्जला व्रत शुरू होगा। रविवार, 15 नवंबर को छठ पूजा का मुख्य आयोजन होगा। व्रती दिनभर उपवास रखकर शाम को जलस्रोतों और घाटों पर पहुंचेंगे तथा अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। बांस के सूप और टोकरी में फल, नारियल, ठेकुआ सहित पूजन सामग्री सजाकर सूर्यदेव की आराधना की जाएगी। सोमवार, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिवसीय व्रत का समापन होगा।

शहर के 18 स्थानों पर होगी पूजा

जबलपुर में छठ पूजा का आयोजन शहर के अलग-अलग इलाकों में सामूहिक रूप से किया जाता है। छठ महासंघ की ओर से जारी प्रमुख पूजा स्थलों की सूची में गौरीघाट, तिलवाराघाट, भटौली घाट, अधारताल तालाब, हनुमानताल, पुराना कंचनपुर तालाब, रांझी एसएएफतालाब, मानेगांव तालाब और ईस्टलैंड खमरिया तालाब शामिल हैं। इसके अलावा घाना खमरिया तालाब, मढ़ई तालाब बिलपुरा, उदय नगर तालाब, तीन पुलिया न्यू कंचनपुर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर, चांदमारी तलैया, टेलीग्राफकॉलोनी रानीताल, गुलौआ चौक और संजीवनी नगर के शाही तालाब में भी पूजा की व्यवस्था की गई है।

अस्त और उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा

छठ पर्व में सूर्यदेव के साथ छठी मैया की पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व की खासियत है कि इसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। श्रद्धालु संतान की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ कठिन निर्जला व्रत रखते हैं। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व आस्था, अनुशासन, स्वच्छता और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है।

आज से शुरू हुआ मोतियाबिंद जांच अभियान, मेडिकल में होंगे ऑपरेशन

23 दिसंबर तक जिले के 14 स्थानों पर लगेंगे शिविर

जबलपुर,यशभारत। ग्रामीण क्षेत्रों में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज द्वारा विशेष अभियान शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला अंधत्व नियंत्रण समिति और मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में 13 नवंबर से 23 दिसंबर तक जिले के विभिन्न विकासखंडों में नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में जांच के दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित पाए जाने वाले मरीजों को मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा मिलेगी। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. नवनीत सक्सेना और अधीक्षक डॉ. अरविंद शर्मा के निर्देशन में नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. पद्मिनी वरखेड़े के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर मरीजों की जांच कर रही है। अभियान का उद्देश्य उन जरूरतमंद मरीजों तक नेत्र चिकित्सा की सुविधा पहुंचाना है, जो आर्थिक या अन्य कारणों से समय पर उपचार नहीं करा पाते। इसके अलावा अस्पताल में रहने, भोजन, दवाइयों और लेंस प्रत्यारोपण का खर्च भी मरीजों से नहीं लिया जाएगा।

23 दिसंबर तक यहां लगेंगे शिविर

नवंबर में 13 नवंबर को बरगी, 16 नवंबर को सिहोरा, 19 नवंबर को मझौली, 25 नवंबर को पाटन, 27 नवंबर को पनागर और 30 नवंबर को शहपुरा में शिविर आयोजित होंगे। दिसंबर में 1 तारीख को बरेला, 3 को चरगवां, 7 को कुंडम, 10 को बेलखेड़ा, 14 को बरगी, 17 को मझगवां, 21 को सिहोरा और 23 दिसंबर को पाटन में जांच शिविर लगाए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों से निर्धारित तिथियों पर शिविरों में पहुंचकर आंखों की जांच कराने और इस निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

केलवा के पात पर उगेलन सुरुजदेव' एवं 'काँच ही बाँस के बहंगिया

पमरे के प्रमुख स्टेशनों पर गूंज रहे छठी मैया के पारंपरिक गीत



जबलपुर यशभारत। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर पश्चिम मध्य रेल द्वारा यात्रियों को पर्व की परंपरा, संस्कृति एवं उल्लास से जोड़ने के लिए विशेष पहल की गई है। इसके तहत जबलपुर, भोपाल एवं कोटा मंडलों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से छठ महापर्व के पारंपरिक लोकगीतों का प्रसारण किया जा रहा है।

इन स्टेशनों में गीतों से वातावरण भक्तिमय हो रहा- जबलपुर मंडल के जबलपुर, मदन महल, कटनी, सतना, मैहर, नरसिंहपुर, पिपरिया, सागर, दमोह एवं रीवा, भोपाल मंडल के भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, बीना एवं गुना तथा कोटा मंडल के कोटा, गंगापुर सिटी, झालावाड़ सिटी, बारां, भरतपुर एवं सवाई माधोपुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर छठी मैया के पारंपरिक गीतों से वातावरण भक्तिमय हो रहा है। 'केलवा के पात पर उगेलन सुरुजदेव' एवं 'काँच ही बाँस के बहंगिया' जैसे लोकप्रिय गीत विशेष रूप से बिहार एवं पूर्वांचल की ओर यात्रा कर रहे यात्रियों को अपनी संस्कृति और घर-परिवार से जुड़ाव का सुखद एहसास करा रहे हैं।



अनंत ब्राह्मण महासभा का परिचय सम्मेलन 15 को

जबलपुर, यशभारत। आगामी 15 नवंबर, रविवार को अनंत ब्राह्मण महासभा द्वारा जबलपुर में एक भव्य युवक-युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। संस्था के राष्ट्रीय संस्थापक एडवोकेट अखिलेश उपाध्याय और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित के. के. शर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन का पंजीयन पूर्णतया निःशुल्क रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले युवतियों के प्रस्ताव अधिक प्राप्त हुए हैं, तथा बाहर से आने वाली युवतियों के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था महासभा द्वारा की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और भगवान परशुराम के पूजन के साथ होगा, जिसके बाद उपस्थित युवक-युवतियों के बायोडाटा का वाचन किया जाएगा। इस अवसर पर 'स्नेह बंधन-2026' पत्रिका का विमोचन भी विशेष रूप से किया जाएगा। पंडित एस.के. पचौरी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य योग्य जीवनसाथी की तलाश कर रहे युवाओं को सही मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम के अंत में दोपहर भोज और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

पूर्व सैनिकों के आरक्षण का मुद्दा गरमाया, 40 हजार जवानों को नौकरी देने की मांग

मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने सरकार की नीति पर उठाए सवाल



भोपाल,यश भारत। मध्यप्रदेश में पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और प्राथमिकता देने की मांग तेज हो गई है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव ने प्रदेश सरकार से पूर्व सैनिकों के हित में ठोस नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में वर्ष 2019 तक ग्रुप-सी में 10 प्रतिशत और ग्रुप डी में 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था लेकिन नियमों में बदलाव के बाद पिछले छह वर्षों में महज 5 से 6 पूर्व सैनिकों को ही इसका लाभ मिला है। श्रीवास्तव के अनुसार प्रदेश में करीब 40 हजार पूर्व सैनिक रोजगार की तलाश में हैं। अधिकांश सैनिक 15 से 17 साल की सेवा के बाद 35 से 40 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है। उन्होंने अग्निवीर योजना के तहत 25 प्रतिशत जवानों को नियमित करने और शेष 75 प्रतिशत के भविष्य पर भी सवाल उठाए।

नगर निगम की वर्कशॉप पर उठे सवाल, क्रेन से खींचकर ले जाई जा रहीं कचरा गाड़ियां

आधी से ज्यादा गाड़ियां खराब होने का आरोप, समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से व्यवस्था पर उठे सवाल

भोपाल,यश भारत।



राजधानी में नगर निगम की कचरा गाड़ियों की बदहाल स्थिति सामने आने के बाद निगम की वर्कशॉप की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि खराब होने वाली कचरा गाड़ियों का समय पर मेंटेनेंस कराने के बजाय अब पूरी तरह बंद हो चुकी गाड़ियों को क्रेन की मदद से खींचकर ले जाना पड़ रहा है। इस स्थिति ने नगर निगम की वर्कशॉप में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर गाड़ियों का नियमित रखरखाव क्यों नहीं किया जा रहा, छोटी-मोटी खराबियों को समय रहते ठीक क्यों नहीं कराया जा रहा आरोप है कि नगर निगम की आधी से ज्यादा कचरा गाड़ियां खराब होकर बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। यदि समय रहते इन वाहनों का मेंटेनेंस किया जाता तो शायद इन्हें इस स्थिति तक पहुंचने से रोका जा सकता था। अब सवाल यह है कि जब नगर निगम के पास वाहनों के रखरखाव के लिए वर्कशॉप और कर्मचारी मौजूद हैं, तो फिर गाड़ियों को क्रेन से खींचकर ले जाने की नौबत क्यों आ रही है इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होना जरूरी है।

भाई दूज पर लाड़ली बहनों को मोहन सरकार का बड़ा तोहफा

शिवपुरी में सिंगल क्लिक से जारी हुई 42वीं किस्त

भोपाल, यशभारत।



मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए भाई दूज का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आया। दीपावली के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की लाखों पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सफलतापूर्वक अंतरित कर दी है। भाई दूज के पावन अवसर पर सरकार की ओर से मिली इस आर्थिक सहायता से महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। लंबे समय से 42वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के खातों में राशि पहुँचने से उन्हें घरेलू जरूरतों, बच्चों की पढ़ाई और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में बड़ी राहत मिली है। शिवपुरी के पिछोर में हुए इस भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर की हितग्राहियों को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार के संकल्प को दोहराया। सरकार की इस प्रमुख योजना के तहत हर महीने सीधे बैंक खातों में राशि पहुँचने से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं।

पराली प्रबंधन को लेकर देर से जागा प्रशासन, खेतों में उतरकर जानी हकीकत

जबलपुर, यश भारत

यशभारत
खबर का असर

खेतों में पराली (फसल अवशेष) प्रबंधन को लेकर यश भारत की खबरों का अब बड़ा असर देखने को मिला है। प्रशासनिक सुस्ती और संसाधनों की कमी पर सवाल उठने के बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा खुद एक्शन मोड में नजर आए और गुरुवार को मैदानी निरीक्षण के लिए निकल पड़े। उन्होंने पनागर विकासखंड के ग्राम उमरिया चौबे और ग्राम नुनिया कला पहुंचकर पराली प्रबंधन के कार्यों का जायजा लिया।

ट्रैक्टर पर बैठकर देखी प्रक्रिया किसानों से की चर्चा

कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने खेतों का भ्रमण कर फसल कटाई के बाद बचने वाले अवशेषों के प्रबंधन के कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेत में स्वयं ट्रैक्टर पर बैठकर बेलर यूनिट से पराली संग्रहण के कार्य को करीब से देखा तथा सुपर सीडर एवं हैप्पी सीडर के माध्यम से बिना पराली जलाए बोनी किए जाने की प्रक्रिया का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से सीधे चर्चा कर पराली प्रबंधन के लिए अपनाई जा रही तकनीकों और उनके अनुभवों की जानकारी ली। उन्होंने किसानों को समझाइश दी कि पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर आधुनिक कृषि यंत्रों के माध्यम से बिना पराली जलाए अगली फसल की बोनी की जा सकती है।

कृषि यंत्र संचालकों और अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर ने मौके पर मौजूद बेलर यूनिट एवं कृषि यंत्र संचालकों से भी संवाद किया। इस दौरान किसानों और संचालकों ने कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधनों की समय पर उपलब्धता तथा खेतों में नमी की स्थिति के अनुसार बोनी करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से उन्हें अवगत कराया। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कृषक संगठनों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं पर चर्चा करें और उनके समाधान के लिए समन्वित प्रयास करें। उन्होंने किसानों को पराली प्रबंधन के लिए समय पर बेलर यूनिट उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।



कलेक्टर ने कहा कि किसानों की बोनी समय पर सुनिश्चित करने के साथ फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन भी जरूरी है। इसके लिए किसानों, कृषि विभाग और कृषि यंत्र संचालकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि खेती को लाभकारी बनाने के साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सके। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण एसडीएम कलावती ब्यारे, कृषि यंत्री जीसी मर्सकोले, कृषि उप संचालक उमेश कटहरे तथा संबंधित अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।



दीनदयाल रसोई में परखी भोजन की गुणवत्ता

जबलपुर, यशभारत।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत जबलपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का दौरा जारी रहा। इसी क्रम में विधायक अशोक रोहाणी और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय तथा नगर निगम आयुक्त अग्रिम कुमार के साथ बड़ा पत्थर, रांझी स्थित दीनदयाल अंत्योदय रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने रसोई में भोजन करने वाले आम नागरिकों से सीधे संवाद कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया और मिलने वाले खाने की गुणवत्ता को परखा। हालात का जायजा लेने के बाद सभी ने रसोई के अंदर पहुंचकर खाना बनने की प्रक्रिया को भी देखा। खास बात यह रही कि औपचारिकता निभाने के बजाय इन सभी ने आम जनता के साथ जमीन पर बैठकर खुद भी वही भोजन किया, जिससे भोजन की असल गुणवत्ता और स्वाद सीधे तौर पर परखा जा सके।

स्वास्थ्य सेवाओं का लिया जायजा

इसी दौरे की अगली कड़ी में मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का दल शहीद भगत सिंह वार्ड क्रमांक 63 के अंतर्गत सर्रा पीपल पहुंचा। यहां स्थित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का निरीक्षण करते हुए स्थानीय स्तर पर मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत टटोली गई। दौरे के दौरान क्लीनिक में मरीजों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता और आम नागरिकों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से जानकारी ली गई, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज सुलभ हो सके।

रिसाली नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल हुई तेज

इस बार रिसाली नगर निगम में 41 कमल खिलाने का संकल्प लेकर जाएं, हर घर तक पहुंचे भाजपा का कार्यकर्ता: अरुण साव

भाजपा ने शुरू की चुनावी बैठक, उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक

उपमुख्यमंत्री ने महापौर सहित सभी वार्डों में ऐतिहासिक जीत का दिलाया संकल्प,

विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव मैदान में उतरेगी भाजपा

यश भारत

रिसाली/दुर्ग। आगामी दिनों में होने वाले रिसाली नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कल रिसाली नगर निगम क्षेत्र के आशीर्वाद भवन में छत्तीसगढ़ शासन के उपमुख्यमंत्री अरुण साव की मुख्य उपस्थिति में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की वृहद बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए महापौर सहित सभी 40 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया गया।

बैठक में मंचासीन अतिथियों के रूप में लोकसभा सांसद विजय बघेल, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, विधायक ललित चंद्राकर, भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र वर्मा, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष राकेश पांडेय, रिसाली नगर निगम चुनाव सह प्रभारी द्वय श्रीमती श्वेता शर्मा एवं आशु चंद्रवंशी, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रीतपाल बेलचंदन, जिला महामंत्री दिलीप साहू, जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी शिवेंद्र परिहार, झुग्गी-झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक एवं मंडल प्रभारी दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष अनुपम साहू एवं राजू जंघेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरे उत्साह, समर्पण और संकल्प के साथ मैदान में उतरना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस बार रिसाली नगर निगम में 41 कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। भाजपा सरकार ने %हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे% के संकल्प



को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किया है। आज छत्तीसगढ़ में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन निरंतर हो रहा है और शासन द्वारा इन कार्यों की नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

साव ने आगे कहा कि रिसाली नगर निगम में वर्तमान में कांग्रेस का महापौर होने के बावजूद क्षेत्र की जनता को अपेक्षित विकास नहीं मिल पाया। विकास के नाम पर केवल कागजी दावे किए गए, जबकि धरातल पर जनता को उसका लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास, पारदर्शिता और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि रिसाली नगर निगम क्षेत्र का कोई भी घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए, जहां भाजपा का कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित प्रत्येक परिवार तक पहुंचें, हितग्राहियों से संवाद करें और भाजपा की विकासपरक सोच को जन-जन तक पहुंचाएं।लोकसभा सांसद विजय बघेल ने कहा कि रिसाली नगर निगम का यह चुनाव केवल महापौर और पार्षद चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि क्षेत्र के भविष्य और विकास की दिशा तय करने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताए। जनता ने कांग्रेस के कार्यकाल में विकास की जो स्थिति देखी है, उसका जवाब इस चुनाव में अपने मताधिकार से देगी। हमें एकजुट होकर प्रत्येक वार्ड में भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत से जुटना है। जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि रिसाली नगर निगम चुनाव भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संगठन की शक्ति हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं। सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ प्रत्येक वार्ड में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संपर्क कर भाजपा के पक्ष में वातावरण तैयार करें। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि रिसाली नगर निगम में विकास और सुशासन की नई शुरुआत करना है। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में कहा जाता था कि कोई सीट जीते ना जीते लेकिन दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस पार्टी जरूर जीतेगी लेकिन आप सभी के अथक प्रयास और मेहनत के दम पर हमने यह इस सीट पर जीत दर्ज की फिर से आप सभी चुनावी रण पर उतरे और फिर से पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएं 7

विधायक चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में विकास और जनकल्याण के कार्य निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। रिसाली नगर निगम में भी जनता बदलाव चाहती है। भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनता से संवाद करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि भाजपा का जनप्रतिनिधि क्षेत्र के विकास, मूलभूत सुविधाओं और जनसमस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगा।

बैठक में उपस्थित सभी नेताओं ने एक स्वर में रिसाली नगर निगम के सभी वार्डों में भाजपा की विजय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया तथा कार्यकर्ताओं से चुनावी अभियान में पूरी सक्रियता और समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया।

सेल जूनियर मैनेजर 2026 की परीक्षा कैंसिल

री-एग्जाम में इन कर्मचारियों को ही मौका

भिलाई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में नॉन-एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैडर में प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सेल प्रबंधन ने JM-2026 प्रमोशन प्रक्रिया के तहत 5 जुलाई 2026 को सभी परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) रद्द करने का फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर धांधली की शिकायत के बाद प्रबंधन ने परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। जबकि सेल के कर्मचारी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। विजिलेंस व एक अन्य कमेटी ने जांच रिपोर्ट सेल प्रबंधन को सौंपा था। कॉरपोरेट ऑफिस के मुताबिक, प्रशासनिक कारणों से 5 जुलाई को आयोजित ष्ट्वङ्क्ष को सभी केंद्रों पर निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

अब दोबारा होगी परीक्षा, तारीख का इंतजार – सेल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि फ्रेश एग्जामिनेशन अथवा री-एग्जामिनेशन की विस्तृत जानकारी अलग से जारी की जाएगी। यानी कर्मचारियों को नई परीक्षा की तारीख, समय और अन्य जरूरी दिशा-निर्देशों के लिए अगले सर्कुलर का इंतजार करना होगा।

हर कर्मचारी नहीं दे सकेगा दोबारा परीक्षा– इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परीक्षा में शामिल होने की पात्रता को लेकर है। प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि नई परीक्षा अथवा पुनर्परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने 5 जुलाई 2026 को आयोजित ष्ट्वङ्क्ष में भाग लिया था और अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। इसका मतलब है कि जो पात्र कर्मचारी पहले आयोजित ष्ट्वङ्क्ष में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें इस नई परीक्षा में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा।

5 जुलाई को कंप्यूटर आधारित परीक्षा हुई थी– गौरतलब है कि नॉन-एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव कैडर (JM-2026) में प्रमोशन के लिए सेल ने 24 अप्रैल 2026 को सर्कुलर जारी किया था। इसी प्रक्रिया के तहत 5 जुलाई को कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। अब प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए उस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है।

सेल के इस फैसले से प्रमोशन परीक्षा में शामिल हुए कर्मचारियों के बीच नई परीक्षा को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। अब सबकी नजर प्रबंधन की अगली अधिसूचना पर रहेगी, जिसमें परीक्षा की नई तारीख और प्रक्रिया स्पष्ट की जाएगी।

छठ पर्व से पहले तालाबों की सफाई में जुटीं महापौर अलका बाघमार, चार तालाबों का किया निरीक्षण



यश भारत

दुर्ग। छठ पर्व को देखते हुए शहर के तालाबों और घाटों की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने महापौर अलका बाघमार ने मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को उन्होंने निगम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ रेवा तालाब, शक्तिनगर तालाब, पुजारी तालाब और कातुलबोर्ड तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान रेवा तालाब में महापौर ने स्वयं फावड़ा चलाकर जलकुंभी और कचरा निकालने में श्रमदान किया। उनके साथ लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर और पार्षद मनोज सोनी ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। महापौर ने अधिकारियों को छठ पर्व से पहले सभी तालाबों और घाटों की युद्धस्तर पर सफाई कराने, जलकुंभी हटाने और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों की सफाई केवल पर्व तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक तालाब की महीने में कम से कम एक बार नियमित सफाई की जाए। निरीक्षण के दौरान पार्षदों, निगम अधिकारियों और कर्मचारियों सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

कबीरधाम जिले में 18 को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस

सांसद श्री संतोष पाण्डेय होंगे मुख्य अतिथि



कवर्धा। कबीरधाम जिले में 18 नवंबर को जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा सहित देश के महान जनजातीय नायकों के अदम्य साहस, संघर्ष, बलिदान और देश की स्वतंत्रता एवं समाज के उत्थान में उनके अतुलनीय योगदान को याद किया जाएगा। कार्यक्रम में सांसद श्री संतोष पाण्डेय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रहेगी। कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति के निर्देश पर जिला स्तरीय आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। संबंधित विभागों को कार्यक्रम की सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करने तथा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आयोजन गरिमामय एवं भव्य तरीके से संपन्न हो सके। जनजातीय गौरव दिवस का उद्देश्य जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के महत्वपूर्ण योगदान को जन-जन तक पहुंचाना है।

हिर्री खदान अस्पताल में ई-सुश्रुत एचएमआईएस लागू, अब मोबाइल पर मिलेगी ओपीडी पर्ची और जांच रिपोर्ट



भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, भिलाई से संबद्ध हिर्री खदान अस्पताल में ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) का क्रियान्वयन शुरू किया गया है। इस व्यवस्था से अस्पताल की चिकित्सा सेवाएं डिजिटल होंगी और मरीजों को कई सुविधाएं मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेंगी। इस प्रणाली को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा लागू किया जा रहा है। इसके तहत ओपीडी, चिकित्सक कक्ष, औषधालय, इंजेक्शन कक्ष और अन्य सेवाओं को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। खास बात यह है कि ई-सुश्रुत प्रणाली को संयंत्र के स्वास्थ्य साथी मोबाइल एप से भी जोड़ा गया है। इसके माध्यम से मरीज अपनी ओपीडी पर्ची, निर्धारित दवाइयों और लैब जांच का विवरण मोबाइल पर देख सकेंगे। वहीं, सेक्टर-9 अस्पताल की प्रयोगशाला में कराई गई जांचों की रिपोर्ट भी एप के जरिए प्राप्त की जा सकेगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. संबिता पंडा के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल में महाप्रबंधक प्रभारी संजय कुमार सहित चिकित्सा अधिकारियों और सी-डैक की टीम का योगदान है। प्रबंधन के अनुसार इस व्यवस्था से कागजी पर्चियों पर निर्भरता कम होगी और मरीजों को अधिक पारदर्शी एवं सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

नपानि की बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव को मिली स्वीकृति, महापौर परिषद ने दी मंजूरी

यश भारत

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त सुरूचि सिंह की उपस्थिति में आहूत की गई। बैठक में निगम के विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा शहर में बेहतर प्रशासनिक एवं मूलभूत सुविधाओं के संचालन को लेकर विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से वाहन शाखा के लिए अस्थायी श्रमिक उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की नियुक्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों को विचारार्थ रखा गया।



बैठक के प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निगम की वाहन शाखा में उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल वाहन चालक तथा हेल्पर उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस कार्य के लिए कुल 1 करोड़ 77 लाख 54 हजार 790 रुपये की संभावित लागत निर्धारित की गई है। उक्त कार्य कराए जाने के संबंध में सलाहकार समिति द्वारा पूर्व में अनुशंसा प्रदान की जा चुकी है। समिति की अनुशंसा के पश्चात जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। महापौर परिषद के सदस्यों ने प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात कार्य कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की। वाहन शाखा में आवश्यकतानुसार वाहन चालक एवं हेल्पर उपलब्ध होने से निगम के वाहनों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। इससे निगम के विभिन्न विभागों में संचालित वाहनों के कार्यों को गति मिलेगी तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन में भी सहूलियत होगी। वार्ड क्रमांक 33 संतोषी पारा शर्मा कॉलोनी में अधो संरचना मद वित्तीय वर्ष 2024-25 में डोम शेड निर्माण कार्य में बची हुई शेष राशि से वार्ड क्रमांक 33 संतोषी पारा कैंपेश्वर बैजनाथ धाम के पास डोम शेड निर्माण कार्य कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई।

इसी प्रकार बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के एक पद पर नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई। संबंधित पद के लिए अंतिम योग्यता सूची जारी की जा चुकी है, जिसमें एक अभ्यर्थी का चयनित सूची में तथा एक अभ्यर्थी का प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल है। महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति किए जाने की अनुशंसा की गई।

बैठक में महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, एकांश बंछोर, नेहा साहू उपस्थित रहे। इसके अलावा अपर आयुक्त राजेन्द्र कुमार दोहरे, उपायुक्त दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, लेखाधिकारी चंद्रभूषण साहू, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, वाहन शाखा प्रभारी शशिकांत वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन एवं देवव्रत राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

छठ पर बिहारियों को लूटने इन्तजार करती रही रेलवे और एयर लाइन्स, इनके बिना बिहारी तरकीब निकल कर पहुँच गए अपने गाँव छठ मनाने

इस बार छठ पर बिहारी ने रोया नहीं, जुगाड़ लगा दिया

तनवीर अहमद

भिलाई (यश भारत)। एयरलाइन कंपनियां बैठी थीं अपने किराया का रेट 'दिल्ली-पटना 18,000,, मुंबई-पटना 26,000,, बेंगलुरु-पटना 35,000' का लिस्ट बनाके सोच रही थीं, बिहारी मजबूर है, देगा ही देगा।

इसी तरह रेलवे बैठा था कि 'वेटिंग 400, कंफर्म होगा ही नहीं'और बिहारी ने क्या किया 22,000 से ऊपर निजी गाड़ियां दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद से निकल पड़ीं बिहार की तरफ!

कार, स्क्रू, टेम्पो, और तो और ऑटो रिक्शा तक!

बेंगलुरु से 4 लड़के 2,200 Kरूऑटो से मोतिहारी पहुंच गए। दिल्ली से 3 लड़के 1,200 Kरूऑटो से 38 घंटे में मधुबनी पहुंच गए।

अखबारों में छपा, लोगों ने मजाक उड़ाया, पर बिहारी हंसा नहीं - घर पहुंच गया।

हिसाब समझिए, गणित बिहारी का है

1 आदमी का हवाई किराया = 18,000 रुपये उसी 18,000 में

पेट्रोल + टोल + खाना = 15,000-18,000

और गाड़ी में 4 लोग निकल लिए! मतलब - फ्लाइट में 1 आदमी = 18,000

कार में 4 आदमी = 18,000

प्रति व्यक्ति पड़ा 4,500 रुपये! और ऊपर से अपना सामान, ठेकुआ, नारियल, सूप, दउरा सब साथ में

रास्ते में जहाँ मन किया रुके, चाय पी, घर के



दरवाजे तक गाड़ी गई, स्टेशन से ऑटो का झंझट नही, वापसी में भी वही गाड़ी काम आएगी

एयरलाइन को लगा था बिहारी लूटेगा, बिहारी ने एयरलाइन को ही लूट से बचा लिया - अपनी जेब को!

रेलवे का भी वही हाल

रेलवे ने इस बार 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई, बिहार के लिए अकेले 106 स्पेशल ट्रेनें, वंदे भारत तक चला दी। फिर भी टिकट नहीं मिला।

क्यों? क्योंकि बिहारी को अब ट्रेन के भरोसे रहना ही नहीं है।

जिसको ट्रेन मिली वो ट्रेन से गया, जिसको नहीं मिली वो गाड़ी से गया, पर छठ पर घर न जाने का ऑप्शन बिहारी के पास है ही नहीं।

छठ बिहारी के लिए त्योहार नहीं, इमोशन है। माँ के हाथ का ठेकुआ, घाट पर अर्घ्य, 36 घंटे का निर्जला व्रत - ये फ्लाइट के 18,000 में नहीं मिलता।

इस बार बिहारी ने 3 इंडस्ट्री को सबक सिखा दिया

एविएशन को डायनामिक प्राइसिंग के नाम पर लूटोगे तो कस्टमर गाड़ी ले लेगा। 3,000 की टिकट 35,000 में बेचोगे तो लोग ऑटो से ही चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी यही मामला चल रहा है।

रेलवे को - हर साल छठ पर वेटिंग का रोना रोते हो, पर 12,000 स्पेशल ट्रेन भी कम पड़ जाती है। मतलब डिमांड इतनी है, सिस्टम उतना नहीं है।।सरकार को - दिल्ली सरकार को 50+ AC बसें चलानी पड़ीं, बिहार सरकार को 155 स्पेशल बसें चलानी पड़ीं। मतलब बिहारी की ताकत देखकर सरकार को भी बसें चलानी पड़ गईं।

असली बात ये है

बिहारी गरीब नहीं है, बिहारी समर्थ है।

जिस बिहारी को लोग 'मजदूर' कहकर चिढ़ाते थे, आज वही बिहारी दिल्ली में 20 लाख की गाड़ी रखता है, बेंगलुरु में IT में है, मुंबई में बिजनेस करता है।

और जब उसको घर जाना होता है, तो वो किसी एयरलाइन या रेलवे के रहम पर नहीं रहता।

वो स्टेयरिंग पकड़ता है, और निकल पड़ता है - 1,200 Kरू 2,200 Kरू.. घर तक

इसलिए इस बार छठ पर -

एविएशन हारी, रेलवे हारी,

जीता तो सिर्फ बिहारी - और उसका जज्बा!

श्रेयस अय्यर सबसे कम एकदिवसीय खेलकर कप्तानी हासिल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल



माउंट माउंगानुई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे एकदिवसीय मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी संभालते ही एक रिकार्ड अपने नाम किया है। वह एकदिवसीय प्रारुप में कमान संभालने वाले 29 वें कप्तान बने है। यह पहली बार है जब उन्होंने 50 ओवर के प्रारूप में टीम की बागडोर संभाली है। इस अहम भूमिका को निभाने से पहले, श्रेयस ने भारतीय टीम की ओर से 85 एकदिवसीय मैच खेले थे। इस प्रकार वह सबसे कम मैच खेलकर कप्तानी हासिल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गये हैं।

श्रेयस का 85 मैचों के बाद ही एकदिवसीय में कप्तानी संभालना भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक रोचक आंकड़ा पेश करता है। भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने पहली बार एकदिवसीय कप्तानी संभालने से पहले 100 या उससे भी अधिक मैच खेले थे। इस सूची में सबसे ऊपर भारतीय क्रिकेट के महान स्पिनर अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 217 एकदिवसीय मैच खेलने के बाद पहली बार भारत की कमान संभाली थी। इस सूची में वीरेंद्र सहवाग ने सबसे कम 70 एकदिवसीय खेलकर कप्तानी की थी, जबकि हार्दिक पंड्या ने 71 एकदिवसीय खेलने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं महेन्द्र सिंह धोनी ने 81 और सुरेश रैना ने 90 मैच खेलकर कप्तानी संभाली थी। इस तरह, 85 वनडे खेलने के बाद कप्तान बने श्रेयस अय्यर, धोनी (81) और रैना (90) के बीच में आते हैं। दिलीप वेंगसरकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 98-98 एकदिवसीय खेलने के बाद कप्तानी हासिल की थी। रोहित शर्मा ने 171 एकदिवसीय , शिखर धवन ने 142 एकदिवसीय और राहुल द्रविड़ ने 138 एकदिवसीय खेलने के बाद इस प्रारुप में कप्तानी हासिल की थी। अजय जड़ेजा ने भी 129 एकदिवसीय खेलकर कप्तानी की भूमिका संभाली थी।वहीं, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 119 एकदिवसीय, सौरव गांगुली और के. श्रीकांत ने 111-111 एकदिवसीय, जबकि विराट कोहली ने 104 और गौतम गंभीर ने 100 एकदिवसीय खेलने के बाद ही पहली बार टीम की बागडोर संभाली थी।

डेब्यू मैच में 28 गेंदों में 5 विकेट; 21 साल के महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ मचाई तबाही

पर्थ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहला वनडे पर्थ में खेला जा रहा है। इस मैच में 21 साल के ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज महली बियर्डमैन महफिल लूट ले गए। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मात्र 28 गेंदों में अपना 5 विकेट हॉल लिया। वह डेब्यू मैच में 5 विकेट हॉल लेने दुनिया के 18वें और ऑस्ट्रेलिया के मात्र दूसरे ही गेंदबाज बने हैं। महली बियर्डमैन से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए 1988 में टोनी डोडेमेड ने श्रीलंका के खिलाफ पहली बार यह कारनामा किया था। वहीं दुनिया में ऐसा श्रीलंका के उवैस करनैन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1984 में किया था। ऐसा नहीं है कि महली ने पुछल्ले बल्लेबाजों के विकेट चटकाए हो, उनके इस 5 विकेट हॉल में जो रूट से लेकर हैरी ब्रूक जैसे धकाड़ बल्लेबाज मौजूद हैं। उन्होंने इन दोनों के अलावा सैम करन, लियाम डेवसन और जॉर्डन क्रॉक का विकेट चटकाया।

महली बियर्डमैन ने अपने वनडे करियर की शुरुआत मेडन ओवर से की थी। दूसरे ओवर में उन्होंने हैरी ब्रूक का तो तीसरे ओवर में जो रूट का विकेट चटकाया। इसके बाद उन्हें चौथे ओवर में जॉर्डन क्रॉक और सैम कुर्रन के रूप में 2 विकेट मिले। उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल पांचवें ओवर में ही लियाम डेवसन का विकेट लेकर पूरा किया।

- पहले ओवर में मेडन।
- दूसरे ओवर में 1 विकेट।
- तीसरे ओवर में 1 विकेट।
- चौथे ओवर में 2 विकेट।
- पांचवें ओवर में 1 विकेट।

महली बियर्डमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ7.4 ओवर में मात्र 24 रन खर्च कर कुल 6 विकेट चटकाए। उनके इस धाकड़ प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड की पूरी टीम 131 रनों पर ही सिमट गई। महली ने जोफ्रा आर्चर के रूप में अपना 6ठा विकेट लिया।



आईपीएल 2027 मिनी नीलामी के लिए मुस्तफिजुर सहित सात बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने नाम दिये

मुम्बई (ईएमएस)। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 के आगामी मिनी नीलामी में इस बार बांग्लादेश के 7 खिलाड़ी शामिल है। जिसमें एक नाम तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का भी है। ये वही मुस्तफिजुर रहमान हैं, जो पिछले सत्र में विवादों में रहने के कारण आईपीएल से बाहर कर दिये गये थे। पिछले साल, आईपीएल 2026 से पहले, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर को अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबरों के मद्देनजर उपजे विरोध प्रदर्शनों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के हस्तक्षेप के बाद, फ्रेंचाइजी ने सीजन की शुरुआत से पहले ही मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया



था। इस घटना ने दोनों देशों के क्रिकेट संबंधों में काफी खटास पैदा कर दी थी और एक बड़ा राजनीतिक-सामाजिक विवाद खड़ा हो गया था। इस घटना के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) की तरफ से भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। भारत द्वारा 2026 टी20 विश्व कप की मेजबानी का बांग्लादेश ने बहिष्कार किया था।

अब, लगभग दस महीने बाद हालातों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। आगामी आईपीएल 2027 सीजन के लिए 16 दिसंबर को होने वाले मिनी निलामी के लिए बीसीसीआई ने विभिन्न क्रिकेट बोर्ड्स से खिलाड़ियों की सूची मांगी थी, जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी शामिल रहा। ऐसे में एक रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के सात खिलाड़ियों ने इस नीलामी के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया है। इसमें मुस्तफिजुर रहमान के अलावा, नाहिद राणा, रिशाद हुसैन, हसन महमूद, तौहीद हृदोय, तस्कीन अहमद और शोरफुल इस्लाम शामिल हैं।आईपीएल प्रबंधन की तरफसे नीलामी में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की आधिकारिक सूची अभी जारी नहीं की गई है। इस सूची को जारी होने में अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि सभी 10 फ्रेंचाइजी पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी करेंगी और रिलीज किए गए खिलाड़ी भी ऑक्शन पूल का हिस्सा बनेंगे।

चीन में पहली बार खेली जाएगी लीजेंड्स टी20 क्रिकेट लीग

बीजिंग (ईएमएस)। चीन में पहली बार क्रिकेट लीग शुरु होने जा रही है। इससे देश में क्रिकेट को व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है। विश्व चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट (डब्ल्यूसीसी) ने चीन के डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स के साथ मिलकर देश की अपनी तरह की पहली फ्रेंचाइजी आधारित लीजेंड्स टी20 लीग शुरू करने की घोषणा की है। आठ टीमों वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का पहला संस्करण मई 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कई दिग्गज पूर्व क्रिकेटर भाग लेंगे। यह कदम चीन में क्रिकेट के विस्तार और विकास के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, जो खेल को एक नए बाजार में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा क्रिकेट के लिए नए बाजारों की तलाश और लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट की वापसी को देखते हुए भी इस लीग का महत्व बढ़ जाता है। खेल जानकारों का मानना है कि यह लीग चीन में क्रिकेट के विकास को गति देने और खेल को नए दर्शकों



तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। इस महत्वाकांक्षी पहल की नींव अक्टूबर 2026 में डब्ल्यूसीसी और डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) से रखी गई थी। गौरतलब है कि डोंग्यूहुई स्पोर्ट्स, जियांग्सू प्रांत के ताइचांग स्थित शाक्सी टाउन क्रिकेट सेंटर का संचालन करता है, जो अपनी स्थानीय विशेषज्ञता और उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के माध्यम से चीन के बढ़ते खेल बाजार तक विश्वस्तरीय क्रिकेट पहुंचाने में सहायक साबित होगा। वहीं, डब्ल्यूसीसी का संचालन अनुभवी प्रमोटर्स द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय फ्रेंचाइजी आधारित खेल प्रतियोगिताओं के विकास और संचालन का व्यापक अनुभव है।

रंग संसार

सलमान की मातृभूमि के ट्रेलर में दिखा दमदार एक्शन



बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म में देशभक्ति, सैनिकों के बलिदान और युद्ध के मानवीय पहलुओं को दिखाया गया है। ट्रेलर में सलमान खान एक ऐसे सैनिक की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो देश की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। फिल्म में एक्शन के साथ भावनात्मक दृश्यों को भी प्रमुखता दी गई है। ट्रेलर की शुरुआत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्रों में शामिल एक बर्फीले इलाके से होती है। यहां हिमस्खलन के खतरनाक दृश्य दिखाई देते हैं। इसी बीच चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तैयारी करते नजर आते हैं। इसके बाद सलमान खान की दमदार एंट्री होती है। वह एक अनुभवी और बहादुर सैनिक के किरदार में दिखाई देते हैं, जिसमें ताकत के साथ समझदारी भी नजर आती है। ट्रेलर में सलमान की निजी जिंदगी की झलक भी दिखाई गई है। अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह फिल्म में उनकी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं। वह अपने पति को सैन्य मिशन पर भेजे जाने को लेकर चिंतित नजर आती हैं। इस दौरान सलमान उन्हें समझाते हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होने वाला आमना-सामना हमेशा गोलीबारी वाली लड़ाई नहीं होता। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का उद्देश्य सैन्य तनाव को बड़े युद्ध में बदलने से रोकना है। फिल्म में सैनिकों की जिंदगी और उनके परिवारों की भावनाओं को भी दिखाया गया है।

देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए ड्यूटी सबसे पहले होती है, लेकिन इसके साथ ही उनके परिवारों को भी कई तरह के भावनात्मक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि सैनिकों के लिए परिवार के साथ बिताया गया हर पल कितना कीमती होता है। सलमान खान अपने एक्शन अवतार में प्रभावशाली नजर आ रहे हैं।

अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने बच्चों के लिए अर्थपूर्ण फिल्में बनाने की अपील की

कहा- बालमन की जिज्ञासा को अपनाना जरूरी

मुंबई (यशभारत)। भारतीय सिनेमा की प्रतिभावान अभिनेत्री रसिका दुग्गल ने बच्चों के मानसिक विकास और मनोरंजन के लिए विशेष रूप से बनाई जाने वाली फिल्मों की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि लिटिल थॉमस जैसी फिल्में बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं, क्योंकि ऐसी कहानियां बाल दर्शकों को अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभवों, मासूम भावनाओं और संवेदनाओं से सीधे तौर पर जोड़ने का अवसर प्रदान करती हैं। इस फिल्म में वे जेसी मिरांडा नामक एक माँ का मुख्य किरदार निभा रही हैं। अभिनेत्री का कहना है कि इस प्रकार का सिनेमा बच्चों का स्वस्थ मनोरंजन करने के साथ-साथ उन्हें सवाल पूछने, रचनात्मक कल्पना करने और अपने आसपास की विशाल दुनिया को अपनी समझ के अनुसार परखने की पूरी आजादी देता है। बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण सिनेमा की जरूरत पर विस्तार से बात करते हुए रसिका दुग्गल ने कहा कि सिनेमा किसी भी व्यक्ति की दुनिया को विस्तार देने और उसकी कल्पनाशीलता को नई उड़ान देने का एक बेहद सशक्त माध्यम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसान के बड़े होने पर उसके मन में जो तमाम तरह के विचार और दृष्टिकोण विकसित होते हैं, उनका गहरा संबंध



अक्सर बचपन के दिनों में देखी गई फिल्मों और कहानियों से होता है। इसी वजह से फिल्म उद्योग को ऐसी कहानियों का निर्माण अधिक से अधिक करना चाहिए, जिनसे बच्चे खुद को भावनात्मक रूप से जोड़ सकें। उन्होंने कहा कि निर्माताओं को बच्चों की सहज जिज्ञासा को नजरअंदाज करने के बजाय उसे खुले दिल से अपनाना चाहिए। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि बच्चों के लिए बनाई जाने वाली फिल्में बिना हल्की-फुल्की या सतही हुए भी बेहद मनोरंजक हो सकती हैं। उन्होंने देश भर के फिल्म निर्माताओं से अपील की कि वे बाल दृष्टिकोण वाली ऐसी कहानियों की खोज करें और उन पर काम करें, जिन्हें बच्चे न केवल खुशी-खुशी देख सकें बल्कि वे कहानियां उनकी रचनात्मक कल्पना शक्ति के लिए नए-नए दरवाजे भी खोलें। कौशल ओझा के निर्देशन में बनी फिल्म लिटिल थॉमस 1990 के दशक के सुंदर राज्य गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह सात साल के मासूम बच्चे थॉमस और उसके परिवार के जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाती है, जिसकी शैली दर्शकों को मालगुडी डेज और रस्किन बॉन्ड की अमर कहानियों की याद दिलाती है। फिल्म में गुलशन देवैया, रसिका दुग्गल और बाल कलाकार हृदांश पारेख ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।



रामायण देखकर निराश हुए नीतीश भारद्वाज, फिल्म की तारीफ वापस लेने का किया ऐलान

टीवी धारावाहिक महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका निभाकर लोकप्रियता हासिल करने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज फिल्म रामायण देखकर निराश हो गए हैं। उन्होंने फिल्म को लेकर पहले की गई अपनी तारीफवापस लेने की घोषणा की है। अभिनेता का कहना है कि रामायण केवल मनोरंजन की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इसके पात्रों और उनके मूल चरित्र को अपनी सुविधा के अनुसार बदलकर प्रस्तुत करना उचित नहीं है। नीतीश भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रामायण भारतीय संस्कृति और चेतना में गहराई से बसी हुई है। इसके नायक, नायिका और खलनायक सभी के चरित्र इस महाकाव्य के मूल संदेश और नैतिक मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा, परंपराओं को बनाए रखने और मर्यादा की स्थापना के लिए राम अवतार लिया था। ऐसे में फिल्म में रावण को असाधारण रूप से उदार, सामाजिक रूप से न्यायप्रिय और निष्पक्ष दिखाना उन्हें पसंद नहीं आया। अभिनेता के मुताबिक, इस तरह का चित्रण रामायण के मूल नैतिक आधार को प्रभावित करता है। इससे भगवान राम के अवतार लेने के उद्देश्य और कहानी के मूल संदेश की महत्ता भी कमजोर हो सकती है।

दिवाली पार्टी में साथ दिखे हिना खान और राजन शाही

मुंबई (ईएमएस)। टीवी अभिनेत्री हिना खान और मशहूर निर्माता राजन शाही की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। दिवाली पार्टी के दौरान दोनों एक ही फ्रेम में नजर आए और साथ में कैमरे के लिए पोज भी दिए। लंबे समय बाद दोनों को इस तरह साथ देखकर प्रशंसक हैरान हैं। तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या दोनों के बीच सालों से चली आ रही नाराजगी अब खत्म हो गई है? यह तस्वीर राजन शाही की बेटी इशिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है। इसमें हिना खान और राजन शाही के साथ कई अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों के एक साथ नजर आने पर कुछ प्रशंसकों ने खुशी जताई, जबकि कई लोग उनके रिश्तों में सुधार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि, इस मुलाकात को लेकर अभी तक हिना या राजन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हिना खान और राजन शाही के बीच पुराने मतभेदों की चर्चा काफी



समय से होती रही है। हिना ने राजन शाही के लोकप्रिय धारावाहिक 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अक्षरा का मुख्य किरदार निभाया था। करीब आठ साल तक इस शो का हिस्सा रहने के दौरान उन्होंने घर-घर में पहचान बनाई। बाद में हिना ने अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए शो छोड़ने का फैसला किया था। वर्ष 2024 में एक इंटरव्यू के दौरान हिना ने शो छोड़ने के अनुभव पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि वह शो के निर्माताओं का सम्मान करती हैं, लेकिन उनका शो से अलग होना अच्छे माहौल में नहीं हुआ था। उनके इस बयान के बाद पुराने विवाद ने फिर सुर्खियां बटोरी थीं। दूसरी ओर, राजन शाही ने भी एक इंटरव्यू में हिना के साथ हुए विवाद पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि हिना शो की स्क्रिप्ट में काफी दखल देती थीं, जिससे सेट पर परेशानियां होती थीं। राजन के मुताबिक, एक बार हिना ने शिवांगी जोशी के किरदार नायरा के समर्थन में कुछ संवाद बोलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मेकर्स ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था और उन्हें सेट छोड़ने के लिए कहा गया था। अब दिवाली पार्टी की तस्वीर ने दोनों के पुराने विवाद को फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, साथ में तस्वीर खिंचवाने से यह स्पष्ट नहीं होता कि उनके बीच मतभेद पूरी तरह खत्म हो गए हैं।

गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं-बहनों और युवाओं का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : साय

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की दर से मिलेगी आदान सहायता राशि : सीएम

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक होगी खरीदी

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में छत्तीसगढ़ निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री ने मुंगेली जिले को दी 465 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

यश भारत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुंगेली जिले के ग्राम कंतेली में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जिलेवासियों को 465 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की लागत के 77 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इनमें 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूर्ण हुए 24 विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 397 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 53 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास किया। इन कार्यों से जिले में सड़क, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना राज्य सरकार का प्रमुख संकल्प है। विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के



लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार भी विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब वहां के गांव मजबूत हों, किसानों को बेहतर संसाधन मिलें, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ें तथा आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हों। मुंगेली जिले में आज जिन विकास कार्यों की सौगात दी गई है, वे इसी सोच को धरातल पर उतारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मुंगेली जिले में अधोसंरचना विकास को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आज लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत के 25 सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया है। इन कार्यों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा तथा किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिलेंगी। अच्छी सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के नए अवसरों का रास्ता भी खोलती हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जल प्रदाय योजना का भूमिपूजन किया गया है। इससे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और नागरिकों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के 40 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 11 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इन कार्यों से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए सिंचाई संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उन्हें खरीफ के साथ रबी एवं अन्य फसलों की खेती के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। इससे फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

अरुण साव पथ विक्रेताओं से करेंगे संवाद, नगरीय प्रशासन विभाग और सूडा द्वारा स्वनिधि महोत्सव का आयोजन

'उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंकों और निकायों का होगा सम्मान, लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे'

'वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान की जानकारी के साथ फूड स्टॉल, प्रदर्शनी, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन'

यश भारत





रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव 14 नवम्बर को राजधानी रायपुर में आयोजित स्वनिधि महोत्सव में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कर रहे पथ विक्रेताओं से सीधा संवाद करेंगे और लाभार्थियों को चेक, यूपीआई पेमेंट बॉक्स तथा प्रशस्ति पत्र वितरित करेंगे। महोत्सव में पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों, उनकी शाखाओं और नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाएगा। महोत्सव में पथ विक्रेताओं को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल भुगतान से जोड़ने विशेष सत्र भी आयोजित किया गया है। इनके साथ ही फूड स्टॉल, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक भी महोत्सव में होंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 'उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम' थीम पर आयोजित स्वनिधि महोत्सव 14 नवम्बर को सुबह दस बजे से साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। महोत्सव का संदेश श्आत्मनिर्भर भारत, सशक्त शहरी विकास, स्वरोजगार से नई संभावनाएंश् रखा गया है।

महोत्सव में उप मुख्यमंत्री अरुण साव लाभार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव जानेंगे। वे पीएम स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों एवं उनकी शाखाओं को सम्मानित करेंगे।

योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली नगरीय निकायों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि महोत्सव में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न बैंकों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारी जानकारी देंगे। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर्स द्वारा डिजिटल भुगतान अभियान के बारे में बताया जाएगा। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक भी होंगे।

स्वनिधि महोत्सव की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप करेंगे। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक सर्वराजेश मूणत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा तथा अनुज शर्मा, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे और सभापति सूर्यकांत राठौर भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मंजूरी प्राप्त निविदा वाले कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी करने के निर्देश

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

यश भारत



रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने आज तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में बस्तर संभाग में आर.आर.पी. और आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए. के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण तथा निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कार्यों में प्रगति नहीं लाने वाले और हीला-हवाला करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए।

बंसल ने सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आर.टी.ओ. और एस.पी. कार्यालयों से समन्वय कर ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने इसके लिए तत्परता से काम कर सड़कों पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सी.आई.आर.एफ. और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।

लोक निर्माण विभाग के सचिव ने पीडब्लूडी मुख्यालय 'निर्माण भवन' में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और अप्लाइंसेस उपयोग करने को कहा। उन्होंने उपकरणों, भवनों एवं परिसंपत्तियों का किफायती रखरखाव सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी बिलों का भुगतान दिसम्बर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी लंबित भुगतानों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा।

बंसल ने सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत/यांत्रिकी और सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यों की निविदा प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने ऐसे कार्यों जिनकी निविदा स्वीकृत हो गई हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों एवं एजेंसियों को जल्द जारी करने को कहा। उन्होंने भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन और मुआवजा प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जून-2027 के पहले मरम्मत किए जा सकने वाले सड़कों की सूची बनाने के निर्देश दिए।

राहुल का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल, 2029 में मोदी के साथ खेलेंगे क्रिकेट और लेंगे उनकी विकेट: रामदास अठावले

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा निशाना, NDA की जीत का जताया भरोसा

यश भारत



रायपुर। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर तीखा बयान दिया।

रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना अब मुश्किल नजर आ रहा है। उन्होंने अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि जब वह कांग्रेस में थे, तब उन्होंने सोनिया गांधी को सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को ढाई साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन उस समय उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया।

अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ खड़ा है और आने वाले चुनावों में भी भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों को जीत मिलेगी।अपने चिर-परिचित अंदाज में राजनीतिक तंज कसते हुए रामदास अठावले ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2029 में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्रिकेट खेलेंगे और राहुल गांधी की विकेट लेंगे।अठावले के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री पद को लेकर सियासी चर्चा तेज होने के संकेत हैं।

गरीबों के निवाले पर डाका: बैज

केवाईसी और सर्वर के बहाने छत्तीसगढ़ के सवा दो लाख परिवारों को पीडीएस राशन से किया गया वंचित

यश भारत



रायपुर। पीडीएस वितरण व्यवस्था में भारी धांधली को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह सरकार बार बार केवाईसी, परिवार के हर सदस्य का सत्यापन और सर्वर की आड़ में गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है, जो सीधे तौर पर आम जनता और गरीबों के अधिकारों पर डाका है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से गरीबों के अधिकारों का हनन रोज़मर्रा की बात बन गई है। केवाईसी और सर्वर की झूठी आड़ लेकर इस सरकार ने प्रदेश के सवा दो लाख से अधिक गरीब परिवारों को उनके हक के पीडीएस राशन से वंचित कर दिया है। इस संवेदनहीन सरकार ने आम जनता के भोजन के अधिकार को छीन लिया है। राजधानी रायपुर के वार्डों में पिछले तीन महीनों से राशन नहीं बंटा है, और पांचवी अनुसूची के हमारे आदिवासी अंचलों से गरीबों के हक का शक्कर और गुड़-चना पूरी तरह गायब कर दिया गया है। यह सरकार डिजिटल व्यवस्था के नाम पर गरीबों के पेट पर लात मार रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि एक सोची- समझी प्रशासनिक लापरवाही और गरीबों के हक में कटौती करने की दुर्भावना है। बायोमेट्रिक और सर्वर फेलियर के नाम पर गरीब राशन कार्डधारियों को परेशान किया जा रहा है। सरकार गरीबों के खाद्यान्न बजट में चुपचाप सेंध लगा रही है।

जनजाति समाज के विकास और उत्थान को देख कांग्रेस पार्टी पीड़ा में : केदार कश्यप

यश भारत



रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पर लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा पलटवार किया है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबाँ में झाँकना चाहिए। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि जिन लोगों ने कभी नक्सलियों को अपना रोल मॉडल बताया था, आज देश से उस पूरे नक्सलवाद का सफाया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। कश्यप ने याद दिलाया कि देश में पृथक जनजाति कार्य मंत्रालय का गठन %भारत रत्न% पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। वहीं, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने %जनजातीय गौरव दिवस% मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और %धरती आबा% के नाम से विशेष योजना शुरू की। इस योजना से हजारों गाँव जुड़े हैं और देश की लगभग आधी जनजाति आबादी यानी करीब 6 करोड़ लोगों को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष और राज्य नेतृत्व को इस बात की पीड़ा है कि जनजाति समाज का अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से तेजी से उत्थान हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में जनजाति समुदाय की उन्नति के लिए कभी ठोस योजनाएँ नहीं बनीं, बल्कि वे जनजाति समाज को दिल्ली और मुम्बई ले जाकर केवल नचाने का काम करते थे। कश्यप ने कहा कि जनजाति समुदाय अब आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस की पुरानी राजनीति अब नहीं चल पाएगी। इसी हताशा और पीड़ा के कारण कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। देश की जनता और विशेषकर जनजाति समाज कांग्रेस की इस मानसिकता को भली-भाँति समझ चुका है। प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने प्रदेशवासियों से आगामी 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में आयोजित होने वाले %जनजातीय गौरव दिवस% समारोह में सपरिवार सम्मिलित होने की अपील की है। कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे जनजातीय महानायकों और शूरवीरों की शौर्य गाथा को जन-जन तक पहुँचाने तथा अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने के उद्देश्य से जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न वरिष्ठ नेतागण, मंत्रिमण्डल के सदस्यगण एवं जनजातीय समाज के लिए विशेष रूप से कार्य करने वाले प्रमुख प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहेंगे।

बाल संरक्षण में छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल, स्कूलों में गठित होंगे 'बाल प्रहरी क्लब'

बच्चे अपने सहपाठियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति बनेंगे सजग प्रहरी

यश भारत



रायपुर। बाल अधिकारों की रक्षा और विद्यालयों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में 'बाल प्रहरी क्लब' गठित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) ने प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों में इन क्लबों के गठन एवं संचालन के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त श्री इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव श्री बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्लब बाल विवाह, बाल श्रम, नशे, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी समस्याओं तथा अधिकारों के उल्लंघन की आशंका के बारे में समय रहते संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे। लगातार अनुपस्थित रहने वाले या संकटग्रस्त बच्चों की पहचान कर उन्हें परामर्श और सहयोग के जरिए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास भी किया जाएगा। प्रत्येक क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह रोकथाम, बाल श्रम उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता तथा साइबर सुरक्षा एवं मानव तस्करी की रोकथाम पांच स्थायी विषय होंगे। शेष पांच विषय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चुने जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

नागरिकों और विद्यार्थियों के आधार व बायोमेट्रिक अपडेट कार्य को दें सर्वोच्च प्राथमिकता-विकासशील

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आधार सेचुरेशन और पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर, स्कूलों में चलाए जाएंगे विशेष अभियान

यश भारत



रायपुर। छत्तीसगढ़ में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से हर पात्र हितग्राही तक पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने आधार से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राज्य में आधार से संबंधित कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पात्र नागरिकों, विद्यार्थियों और आंगनबाड़ियों में दर्ज बच्चों के अभिभावकों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए।

मुख्य सचिव ने स्कूली बच्चों के आधार पंजीयन और बायोमेट्रिक अद्यतन की समीक्षा करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग और संबंधित एजेंसियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले, इसके लिए आधार का होना अनिवार्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार नामक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही, बच्चों की आयु के आधार पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का नए आधार नामांकन, 5 और 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अस्पतालों में जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले ही अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए।

राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के शत-प्रतिशत आधार नामांकन को सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ आदिवासी बसाहटों और ग्राम पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। राज्य सत्यापन पोर्टल पर 18 वर्ष से अधिक आयु के नए नामांकन और 100 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आधार डेटा के सत्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव विकासशील ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवा केंद्रों की सुलभता बढ़ाई जाए ताकि किसी भी नागरिक को असुविधा न हो।

बैठक के अंत में आधार की उपयोगिता को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण के उपयोग से प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक शासकीय सहायता का त्वरित लाभ पहुँचेगा।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, गृह विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया सहित विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी प्रकाशक मुद्रक आशीष कुमार शुक्ला , मिशन मीडिया (प्रा.लि.) प्लाट नम्बर -9/1 छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स,रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ -492001 से मुद्रित एवं हॉउस नम्बर 18/303 सेक्टर 27 ,नवा रायपुर ,रायपुर छत्तीसगढ़ -492018 से प्रकाशित। संपादक आशीष कुमार शुक्ला सलाहकार संपादक श्याम कटारे
प्रबंध संपादक अजय क्षत्रे, स्थानीय संपादक अरविंद कुमार पांडेय मो .-9827117441 RNI-CTHI/26/A5 206 ईमेल -raipuryashbharat@gmail.com (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) , सिटी ऑफिस- आर्यन टॉवर द्वितीय तल द्रोणाचार्य स्कूल के पास रायपुर, मो .-9111201000 (न्यायालय क्षेत्र अधिकार रायपुर)